घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 229- शनिवार 20- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पीएम मोदी ने 15 लाख युवाओं को दिया 2400 करोड़

कहा...विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख जॉब दिए,भविष्य की वर्कफोर्स तैयार कर रही

नई दिल्ली,19 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए खातों में भेजी गई। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए इस इवेंट में प्रधानमंत्री ने युवाओं और उन्हें नौकरियां देने वाले उद्यमियों से संवाद भी किया। पीएम बोले कि यह योजना पहली बार नौकरी खोजने वाले युवाओं और इंडस्ट्री के बीच एक पुल का काम करती है। इसके जरिए हम भविष्य के लिए एक मजबूत वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। इंटेंसिव ट्रांसफर करने का कार्यक्रम देशभर के 200 औद्योगिक क्लस्टर में हुआ। इस कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए, क्योंकि नए लेबर कोड के तहत अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है। गौरतलब है कि PM-VBRY के तहत सरकार ने कुल 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके तहत 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है।

पीएम मोदी की स्पीच की बातें...

- मैं कुछ ही घंटे पहले फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से आया हूं और जी7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट,स्किल और सशक्त की चर्चा सब दूर तक हो रही है।
- हमारी कोशिश है कि भारत का युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हुई है। यह बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देनी वाली योजना है।
- करीब 2 मिलियन युवाओं ने अपनी पहली नौकरी में छह महीने पूरे कर लिए हैं, और आज,इनमें से करीब 1 मिलियन युवाओं को अपनी पहली नौकरी में छह महीने पूरे करने के बाद इस स्कीम के बेनिफिशियरी के तौर पर इंसेंटिव मिला है।
- एक समय था जब देश में केवल 500 के करीब स्टार्टअप थे। आज,2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, और वे देश के हर जिले में मिल जाएंगे। ये आंकड़े भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेंगे।
- दुनिया भविष्य की तकनीक की ओर बढ़ रही है,और भारत अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने का काम कर रहा है। यह भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है,और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासी घमासान

सीएम योगी बोले-एसआईटी जांच से सब साफ हो जाएगा

अयोध्या,19 जून 2026। राम मंदिर के चढ़ावा विवाद को लेकर सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहां रुदौली विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 378 करोड़ रुपये से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विवाद पर सख्त और स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसी के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें एसआईटी को सौंप दें।

एसआईटी जांच से होगा दूध का दूध, पानी का पानी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर ही विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी निष्पक्षता से की जाएगी और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने सभी पक्षों से अपील की कि जांच पूरी होने तक बिना सबूत के बयानबाजी न करें और किसी के चरित्र हनन का प्रयास न करें।

विपक्ष पर तीखा हमला : सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज रामभक्तों का अपमान होने की बात कर रहे हैं, वे पहले राम मंदिर निर्माण

रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। साथ ही कारसेवकों पर गोली चलवाने वालों को आज उपदेश देने वालों का दोहरा चरित्र बताया।

राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष का प्रतीक: मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष चला है और करोड़ों राम भक्तों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में अयोध्या और राम मंदिर को बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ-साथ आस्था और सुशासन दोनों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंदौर में नीट छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत...तीन बार फेल होने और परीक्षा रद्द होने से थी तनाव में

इंदौर,19 जून 2026। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

यानी नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक 22 साल की छात्रा की तीसरी मंजिल से नीचे गिरने के कारण मौत हो गई। गंभीर हालत में छात्रा को पहले एक निजी अस्पताल और फिर एमवाय हॉस्पिटल ले जाया गया,जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान अवंतिका मौर्य के रूप में हुई है, जो धार जिले की रहने वाली थी। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अवंतिका भंवरकुआं की धाकड़ कॉलोनी में एक निजी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर अपनी बड़ी बहन डॉ. सपना मौर्य के साथ रह रही थी। गुरुवार की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे वह मोबाइल फोन पर अपनी चचेरी बहन से बात कर रही थी। बातचीत के दौरान ही वह सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल की छत पर चली गई और वहां से अचानक नीचे आ गिरी। तेज आवाज सुनकर बिल्डिंग के लोग और सुरक्षाकर्मी बाहर भागे। अवंतिका के नीचे गिरते ही गेट पर खड़ा एक युवक दौड़कर उसके पास पहुंचा और तुरंत एम्बुलेंस व पुलिस को सूचना दी गई। अवंतिका की बड़ी बहन डॉ. सपना ने पुलिस को बताया कि वह पिछले तीन साल से नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन तीन बार परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। इस बार उसका पेपर काफी अच्छा गया था और उसे डॉक्टर बनने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन हाल ही में परीक्षा विवाद और पेपर रद्द होने की खबरों के बाद से वह गहरे डिप्रेशन यानी तनाव में चली गई थी।

सुप्रीम कोर्ट से सीएम विजय को राहत! विश्वास मत में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली,19 जून 2026। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई को हुए विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग वाली

याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि यह दावे की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के 'अस्पष्ट, अनर्गल और आरोपों' पर आधारित है। बेंच ने साफ कर दिया कि वह याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तमिलनाडु में 13 मई को, सी जोसफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार ने द्रविड़ मुनेत्र कझगम (द्रमुक) के वॉकआउट के बीच अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (अन्नाद्रमुक) के 25 बागी विधायकों के समर्थन से विश्वास मत हासिल कर एक बड़ी बाधा को पार कर लिया था। टीवीके 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी,लेकिन विजय सरकार बनाने के लिए कांग्रेस,विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके),भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) से समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे, जिससे 120 विधायकों को इकट्ठा कर 118 के आंकड़े को पार कर लिया। विपक्ष ने विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए थे जिन्हें विजय ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता के के रमेश की तरफ से पेश हुए वकील ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टियां पूरे देश में हॉर्स-ट्रेडिंग में लगी हुई हैं।

शादी में डांस के दौरान डांसर की गोली मारकर हत्या,जांच में जुटी पुलिस

पटना,19 जून 2026। बिहार के गोपालगंज से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जिले में एक शादी समारोह में 32 साल के डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती स्टेज से ले जाने की कोशिश की थी और उसने इसका विरोध किया था। कटैया पुलिस स्टेशन इलाके के पटोहवा गांव में गुरुवार देर रात वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के महुआ पाटन गांव के रहने वाले सोनू गौड़ के तौर पर हुई है। पुलिस और परफॉर्मिंग ग्रुप के सदस्यों के अनुसार, उत्तर प्रदेश से एक बारात महेंद्र कुशवाहा के घर आई थी, जहां रामायण यादव की ओर से संचालित एक स्थानीय डांस-ड्रामा ग्रुप की ओर से डांस प्रोग्राम किया जा रहा था। कई गाने पेश करने के बाद महिलाओं के भेष में डांस करने वाला सोनू स्टेज के पास आराम कर रहा था, तभी कुछ मनचले युवक उनके पास आए और एक और परफॉर्मेंस की मांग की। आरोप है कि इसके बाद उन युवकों ने उसे जबरन किसी सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश की।

राजस्थान में टेलीग्राम पर नीट का पेपर बेचने वाला गिरफ्तार

अमेरिकी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था,दिल्ली हाईकोर्ट बोला-टेलीग्राम पर रोक जारी रहेगी

भीलवाड़ा में री-नीट से पहले टेलीग्राम पर बोगस पेपर बेचता युवक गिरफ्तार, वीपीएन के जरिए चला रहा था नेटवर्क

नई दिल्ली,19 जून 2026। टेलीग्राम पर रोक के बाद भी राजस्थान के भीलवाड़ा से नीट का फर्जी पेपर बेचने की कोशिश की गई है। री-नीट परीक्षा से पहले गुरुवार देर रात भीलवाड़ा पुलिस ने टेलीग्राम पर नीट का बोगस पेपर ऑनलाइन बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी वीपीएन के जरिए टेलीग्राम संचालित कर फर्जी पेपर का सौदा कर रहा था। भ्रामक सामग्री फैलाने और अभ्यर्थियों को गुमराह करने के आरोप में पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक सागर राणा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि री-नीट परीक्षा को लेकर बोगस और फर्जी पेपर लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सूचना के आधार पर भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना प्रभारी सुनील ताड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पटेलनगर क्षेत्र में एक

मकान की घेराबंदी कर दबिश दी। मौके पर आकाश चौधरी नामक युवक टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी पेपर ऑनलाइन बेचता मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके बैंक खाते की जांच की, जिसमें करीब 18 हजार रुपए मिले हैं। पुलिस आरोपी से देर रात तक पूछताछ करती रही। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेशी नेटवर्क और वीपीएन का उपयोग कर टेलीग्राम चला रहा था तथा उसके माध्यम से बोगस प्रश्न पत्र बेचने की कोशिश कर रहा था। युवक को रिमांड पर लिया गया है। री-नीट परीक्षा आगामी 21 जून को आयोजित होनी है। परीक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदेश के सभी जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करने तथा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला...टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक जारी रहेगी

टेलीग्राम ऐप के 15 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जून से पहले ऐप से बैन हटाने से इनकार करते हुए टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका रद्द कर दी है। अदालत ने सरकार के कदम को सही बताया है। जस्टिस तेजस करिया ने ढ्रञ्ज एक्ट के सेक्शन 69 के तहत जारी ऑर्डर के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इससे पहले जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल इसलिए कि कुछ यूजर्स परीक्षा दे रहे हैं,मैसेजिंग ऐप के 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है? नीट की परीक्षा से पहले ऐप के गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐप पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी। टेलीग्राम की ओर से अदालत में इसे चुनौती दी गई। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नीट-यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी। लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया। सीबीआई पेपर लीक की जांच कर रही है। 21 जून को दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। प्रश्नपत्रों को इस बार जहां एयर फोर्स के विमानों से भेजा गया है तो टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई।

56 साल के हुए राहुल गांधी,पीएम मोदी ने जन्मदिन पर दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली,19 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 56 साल के हो गए। उनका जन्म साल 1970 में हुआ था। राहुल ने महज 14 साल की उम्र में अपनी दादी इंदिरा गांधी को खो दिया था। इसके बाद उनके पिता की भी हत्या कर दी गई थी। इस राहुल काफी छोटे थे। लंबे समय बाद राहुल ने 2004 में राजनीति में कदम रखा और अब वह विपक्ष का सबसे अहम चेहरा हैं। हालांकि, राहुल के राजनीति में आने के बाद से कांग्रेस पार्टी एक-एक कर अधिकतर राज्य खो चुकी है। अब केरल, कर्नाटक और हिमाचल जैसे चुनिंदा राज्यों में ही कांग्रेस सत्ता में है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर

शुभकामनाएं। उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। केरल में कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर राहुल के राजनीतिक सफर और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके कमिटमेंट की तारीफ करते हुए मैसेज और तस्वीरें शेयर कीं। राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर रोजी एम जॉन ने गांधी को एक ऐसा लीडर बताया, जिन्होंने आज के भारतीय राजनीतिक इतिहास में बेमिसाल संकटों, बुरे चरित्र हनन कैंपेन और बदनाम करने वाले हमलों का सामना किया।

कोयला तस्करी मामले में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार

कोलकाता,19 जून 2026। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित करोड़ों रुपए के कोयला तस्करी मामले में संलिप्तता के आरोप में पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी लंबे समय से उन पर नजर बनाए हुए थी। सूत्रों के अनुसार, कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए मंडल कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित ईडी के साल्ट लेक ऑफिस पहुंचे थे। लंबी पूछताछ के बाद गुरुवार देर रात ईडी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूरी पूछताछ के दौरान मंडल लगातार अपने ही बयानों को बदलते रहे और अधिकारियों के कुछ सवालों का जवाब देने से भी इनकार कर दिया। अब मंडल को कोलकाता में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और सेंट्रल एजेंसी के वकील इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए उनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे।

होर्मुज से हटाई गई अमेरिकी नाकेबंदी

ट्रंप बोले...हम शांति के लिए पूरी तरह कमिटेड

नई दिल्ली,19 जून 2026। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद अब होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी आधिकारिक तौर पर हटा ली गई है। पिछले 66 दिनों से जारी इस कड़े सैन्य प्रतिबंध के हटने को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, नाकेबंदी खत्म होने के बावजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया है कि उनके नौसैनिक जहाज अभी भी उस इलाके में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। कमांड का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शांति समझौते की शर्तों का पालन पूरी ईमानदारी से हो रहा है और क्षेत्र में शांति बहाली की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहे। यह तैनाती किसी आक्रामकता के लिए नहीं, बल्कि समझौते की निगरानी और सुरक्षा के लिए है। इस शांतिपूर्ण बदलाव के

बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका वैश्विक शांति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने मध्य-पूर्व के सभी पक्षों से अपील की है कि वे शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के संकल्प पर कायम रहें। ट्रंप ने कहा, 'हम क्षेत्र के सभी लोगों से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के वादे पर बने रहने की उम्मीद करते हैं।' उनके इस बयान के पीछे की खुशी बाजारों में भी साफ देखी जा रही है; तेल की गिरती कीमतें और शेयर बाजार में आती तेजी यह संकेत दे रही है कि दुनिया ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है। ट्रंप ने लेबनान, हिज्बुल्लाह और इजरायल समेत सभी मोर्चों पर पूर्ण और स्थायी युद्धविराम की उम्मीद जताई है। होर्मुज स्ट्रेट की यह नाकेबंदी अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक लंबा सैन्य संघर्ष था।

बंदर जेवर उठा ले गए...कोर्ट में बोली पुलिस,जज हुए हैरान

लखीमपुर,19 जून 2026। यूपी के लखीमपुर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पहले पुलिस ने अदलत में दावा किया कि बंदरों ने पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में रखे सोने के गहनों को बिखेर दिया और फिर उन्हें लेकर भाग गए। पुलिस ने अब इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है और दावा किया है कि उस वक्त के मालखाना इंचार्ज की मौत हो चुकी है और मामले की जांच संभव नहीं है। दिलचस्प बात ये है कि घटना के वक्त मालखाना इंचार्ज का नाम (जैसा कि कोर्ट के आदेश में बताया गया है) और 17 जून को लखीमपुर पुलिस द्वारा जारी क्लोजर रिपोर्ट को लेकर प्रेस को दिए बयान में जो बताया गया है। वो दोनों नाम अलग-अलग हैं। दरअसल,ये पूरा मामला साल 2007 के एक दहेज हत्या के मुकदमे से जुड़ा है, जिसके आभूषण (अंगूठी, नथुनी, चूड़ियां और हार) कोतवाली सदर के मालखाने में जमा थे। फरवरी 2024 में जब अदालत ने पति को इस मामले में बरी कर दिया, तो उसने अपने पारिवारिक आभूषणों को वापस पाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। इसके जवाब में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 2013 में बारिश की वजह से गहनों वाली

कपड़े की पोटली भीग गई थी,जिसे सुखाने के लिए मालखाने की छत पर रखा गया था,जहां बंदरों ने पैकेट को फाड़कर सारे गहने बिखेर दिए और गहने लापता हो गए। वहीं, जुलाई 2024 में पुलिस की इन बातों को सुनने के बाद जिला जज ने पुलिस जांच का आदेश दिया था। आदेश में साफ़ तौर पर कहा गया कि बंदरों द्वारा गहने चुराने और बिखेरने का दावा अविश्वसनीय है और सोने के गहनों को बारिश के बाद सूखने के लिए बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं था। कोर्ट ने 17 सितंबर 2013 की थाना केस डायरी एंट्री पर भी ध्यान दिया, जिसमें लिखा था कि जोनल आईजी के निरीक्षण के बाद 2013 तक के पोस्टमार्टम पैकेट छत पर रखे गए थे और फिर बंदरों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया और बिखेर दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में खास तौर पर कहा कि पैकेट को सूखने के लिए बाहर रखने का दावा स्वीकार्य नहीं लगता,क्योंकि पैकेट में सोना था जो पानी से खराब नहीं हो सकता और वहां दूसरी पोटलियां भी थीं,जिनमें गंभीर अपराधों के अहम सबूत थे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को जांच करने का निर्देश दिया,क्योंकि स्पष्टीकरण से ऐसा लग रहा था कि गहने गायब मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों ने मालखाने से कीमती सामान निकाल लिया था और सच छिपाने के लिए झूठी डायरी रिपोर्ट बनाई थीं। इस मामले को और दिलचस्प बनाने वाली बात ये है कि जुलाई 2024 के कोर्ट आदेश में उस वक्त के मालखाना इंचार्ज द्वारा दाखिल रिपोर्ट का जिक्र है। उन्होंने परिवार की अर्जी का जवाब देते हुए दावा किया कि गहनों वाला संबंधित पोस्टमार्टम पैकेट रिकॉर्ड में आगे नहीं सौंपा गया था। इस रिपोर्ट में चार पूर्व मालखाना इंचार्ज-मोल्हेराम, रमाकांत तिवारी, मेवाराम और ईश्वर दयाल के नाम हैं,जिनमें से आखिरी व्यक्ति की मौत हो चुकी है।

पासपोर्ट सेवा तेज,सुलभ और वास्तव में लोकतांत्रिक बन चुकी है : एस. जयशंकर

नई दिल्ली, 19 जून 2026। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शुक्रवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आज पासपोर्ट सेवा तेज, सुलभ और वास्तव में लोकतांत्रिक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि विश्वभर में भारतीय प्रतिभा की मांग और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सुगम और प्रभावी पासपोर्ट सेवाएं एक समृद्ध, वैश्विक रूप से जुड़े विकसित भारत की महत्वपूर्ण आधारशिला बनेंगी। जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति देश को 'विश्व बंधु' के रूप में स्थापित कर रही है। इसके कारण भारतीय पासपोर्ट को दुनिया भर में सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पासपोर्ट प्राप्त करना

संघर्ष का विषय नहीं बल्कि नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में पासपोर्ट जारी करने का आंकड़ा 138 लाख से अधिक पहुंच गया है। यह भारतीय नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं और वैश्विक अवसरों की ओर उनके बढ़ते कदमों को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देशभर में केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे और वार्षिक पासपोर्ट जारी करने की संख्या 83 लाख थी। सरकार के व्यापक विस्तार अभियान के परिणामस्वरूप अब 544 कार्यरत केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 454 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शामिल हैं।

संपादकीय

प्रतिगामी है जनसंख्या प्रोत्साहन नीति

हाल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की नई जनसंख्या प्रबंधन नीति के अंतर्गत तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में दूसरे बच्चे के जन्म पर पहले से ही 25 हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। ऐसे फैसलों के पीछे की वजह राज्य की गिरती 'कुल प्रजनन दर' और जनसांख्यिकीय असंतुलन की चुनौतियों से निपटना है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर देखें तो यह कदम लोकसभा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व घटने की आशंका और असुरक्षा की उपज है। संभव है कि जनसंख्या में संकुचन से जूझ रहे अन्य प्रदेश विशेषकर दक्षिणी राज्य भी आंध्र की यह राह पकड़ सकते हैं। ऐसा कोई प्रोत्साहन नितांत संकुचित सोच का ही परिणाम है, जिसमें राज्य के हित को राष्ट्र हित से ऊपर देखा जा रहा है। यह गिरती प्रजनन दर की सतही समझ और जनसांख्यिकीय असंतुलन के शार्टकट समाधान से अधिक कुछ नहीं है।

नायडू की गिनती प्रगतिशील नेताओं में होती है और अतीत में वे समेकित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने के पैरोकार भी रहे हैं,लेकिन उनका यह निर्णय प्रतिगामी है। यह राष्ट्रीय हितों के बरक्स वोट बैंक की राजनीति और प्रभावी दबाव समूह बने रहने की चाह का प्रतिफलन है। नायडू का यह सोच उन वर्गों का हौसला ही बढ़ाएगा,जो अपनी संख्या से राजनीतिक वर्चस्व की चाह रखते हैं। अगर जनसंख्या में कमी को एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है तो फिर उसके उचित समाधान तलाशने होंगे। इसकी एक वजह बड़ी संख्या में युवाओं का समय पर विवाह न करना है। अगर देरी से विवाह हो भी जाए तो वे एक ही संतान को पर्याप्त समझने लगे हैं।

आज के प्रतिस्पर्धा से भरे जीवन और संयुक्त परिवारों के घटते चलन में बच्चों के पालन-पोषण की चुनौतियां कहीं अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे पहलुओं ने भी प्रजनन दर को प्रभावित किया है और एक हद तक इससे जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति भी निर्मित हो रही है। चूंकि भारत में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है तो घटती जनसंख्या वाले राज्यों को अपने राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी चिंता सता रही है। यह आशंका सिर्फ राज्यों की ही नहीं है, बल्कि तमाम धार्मिक और जातीय समुदायों में भी फैल रही है। ऐसी चिंताओं के बावजूद जनसंख्या बढ़ाने संबंधी प्रोत्साहन उचित नहीं,क्योंकि भारत में संसाधन और सुविधाएं सीमित हैं। इन सीमित संसाधनों पर पहले ही भारी जनसंख्या का दबाव है।

जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करें तो जनसंख्या और मानव संसाधन में अंतर होता है। कमाने वाले हाथों और आश्रितों के बीच सही संतुलन आवश्यक है। वर्तमान युग तो मशीन और तकनीक का है। इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्यधिक विकसित तकनीकी उपकरणों वाले युग में तो कमाने वाले हाथों को सोचने वाले मस्तिष्क ने काफी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है। जनसंख्या को मानव संसाधन बनाने के लिए आधारभूत ढांचे,साधन-संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार,पेयजल,समुचित स्वास्थ्य, स्तरीय शिक्षा और कौशल विकास की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं द्वारा ही जनसंख्या को मानव संसाधन बनाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश की तो बात ही क्या, किसी विकसित देश में भी ये संसाधन और सुविधाएं असीमित नहीं।

कृषि भूमि और उसकी उत्पादन क्षमता, अन्यान्य प्राकृतिक संसाधन और यहां तक कि शुद्ध जल और वायु भी असीमित नहीं हैं। साधन-सुविधाओं के अभाव और बढ़ते अपराध के अंतर्संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि,अशिक्षा,गरीबी,कुपोषण,पर्यावरण असंतुलन और प्राकृतिक क्षरण के दुष्चक्र से हम सब अनभिज्ञ भी नहीं हैं। तमाम सुविधाओं के अभाव और संसाधनों पर निरंतर बढ़ते दबाव ने न सिर्फ मानव-स्वभाव और चरित्र को विकृत किया है,बल्कि प्रकृति के स्वरूप को भी बदरंग और विध्वंसक बना डाला है। अत्यधिक दोहन और शोषण ने मनुष्य को प्रकृति का दुश्मन बना दिया है और यही कारण है कि नियमित अंतराल पर प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ी है। प्रख्यात अर्थशास्त्री माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण और प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्संबंध की विस्तृत विवेचना की ही है।

जिस घर में बुजुर्ग हैं,वही है असली घर...

डॉ. विजय गर्ग
मलोट,पंजाब

किसी भी भवन की मजबूती उसकी ऊँची दीवारों,सुंदर सजावट या भव्य स्वरूप से नहीं,बल्कि उसकी मजबूत नींव से आंकी जाती है। नींव दिखाई नहीं देती,लेकिन वही पूरे भवन का भार अपने ऊपर उठाए रखती है। यदि नींव कमजोर हो जाए तो भवन चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो,वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यही स्थिति परिवार की भी है। परिवार रूपी भवन की नींव हमारे बुजुर्ग होते हैं। वे जीवन के अनुभव,ज्ञान, संस्कार, धैर्य और त्याग के ऐसे स्रोत हैं,जिनके कारण परिवार मजबूत, संगठित और संस्कारित बना रहता है।

आज के आधुनिक युग में भौतिक सुख-सुविधाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। लोगों की जीवनशैली तेजी से बदल रही है,संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवार लेते जा रहे हैं और रिश्तों में औपचारिकता बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में बुजुर्गों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है,क्योंकि वे परिवार को उसकी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। वे केवल परिवार के सदस्य नहीं,बल्कि उसकी आत्मा और पहचान होते हैं।

बुजुर्ग :अनुभवों का विशाल भंडार

बुजुर्ग जीवन के विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने दशकों तक जीवन के विभिन्न पाठ पढ़े होते हैं। उन्होंने संघर्ष,सफलता,असफलता,खुशी और दुःख के अनेक रंग देखे होते हैं। उनके अनुभव किसी पुस्तक या इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं।

जब युवा पीढ़ी जीवन की समस्याओं में उलझ जाती है,तब बुजुर्गों का अनुभव उन्हें सही दिशा दिखाता है। चाहे आर्थिक संकट हो,पारिवारिक विवाद हो या सामाजिक चुनौती,बुजुर्गों की सलाह अक्सर परिस्थितियों को सरल बना देती है। वे जानते हैं कि कठिन समय में धैर्य कैसे रखा जाता है और समस्याओं का समाधान कैसे खोजा जाता है।

उनका अनुभव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होता,बल्कि वह परिवार और समाज के विकास में भी सहायक होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के जाने से केवल एक व्यक्ति नहीं,बल्कि अनुभवों का एक विशाल पुस्तकालय समाप्त हो जाता है।

संस्कारों के संवाहक

परिवार की पहचान केवल उसके सदस्यों से नहीं होती,बल्कि उसके संस्कारों और मूल्यों से होती है। इन संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का सबसे बड़ा कार्य बुजुर्ग करते हैं। दादा-दादी और नाना-नानी बच्चों को कहानियों,किस्सों और अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देते हैं। वे बच्चों को सत्य, ईमानदारी,करुणा,सहयोग,सम्मान और अनुशासन जैसे गुण सिखाते हैं। आज जब बच्चों का अधिकांश समय मोबाइल,टीवी और इंटरनेट के बीच बीतता है, तब बुजुर्ग ही उन्हें मानवीय मूल्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं।

बुजुर्ग परिवार की परंपराओं,त्योहारों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक होते हैं। वे बच्चों को बताते हैं कि हमारे रीति-रिवाजों का क्या महत्व है और हमारी संस्कृति हमें क्या संदेश देती है। इस प्रकार वे सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

परिवार को जोड़ने वाली कड़ी

परिवार में विभिन्न आयु और विचारों के लोग रहते हैं। कई बार पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है। ऐसे समय में बुजुर्ग परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे परिवार में प्रेम, सामंजस्य और एकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जब किसी सदस्य के बीच मतभेद होता है,तब बुजुर्ग अपनी समझदारी और निष्पक्षता से विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। उनकी उपस्थिति परिवार को टूटने से बचाती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है।

संयुक्त परिवार व्यवस्था में बुजुर्गों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। वे सभी सदस्यों को एक सूत्र में बाँधकर रखते हैं और परिवार की सामूहिक पहचान को बनाए रखते हैं।

त्याग और समर्पण का प्रतीक

हर बुजुर्ग के जीवन में संघर्षों की एक लंबी कहानी होती है। उन्होंने अपने बच्चों के पालन-पोषण,शिक्षा और भविष्य के लिए अनेक त्याग किए होते हैं। कई बार उन्होंने अपनी इच्छाओं और सपनों का बलिदान देकर अपने परिवार को आगे बढ़ाया होता है।

माता-पिता अपने बच्चों के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं,उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब वही माता-पिता बुजुर्ग हो जाते हैं,तब उनका सम्मान और देखभाल करना बच्चों का नैतिक कर्तव्य बन जाता है।

दुर्भाग्यवश आज कई बुजुर्ग उपेक्षा और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति केवल सामाजिक नहीं,बल्कि मानवीय संवेदनाओं के लिए भी चिंता का विषय है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, उन्हें बुढ़ापे में सहारे की आवश्यकता होती है।

बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में योगदान

बुजुर्ग बच्चों के लिए जीवंत प्रेरणा होते हैं। उनके साथ समय बिताने से बच्चों में संवेदनशीलता, धैर्य और सम्मान की भावना विकसित होती है। वे बच्चों को केवल शिक्षा नहीं देते,बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं।

दादा-दादी की कहानियाँ बच्चों की कल्पनाशक्ति को बढ़ाती हैं। उनके अनुभव बच्चों को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराते हैं। जिन बच्चों का अपने बुजुर्गों से गहरा जुड़ाव होता है,वे प्रायः अधिक भावनात्मक रूप से संतुलित और संस्कारित होते हैं।

आधुनिक समाज और बुजुर्गों की चुनौतियाँ

तेजी से बदलते समाज में बुजुर्गों के सामने अनेक चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं। संयुक्त परिवारों के टूटने,रोजगार के लिए पलायन और व्यस्त जीवनशैली के कारण कई बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं।

तकनीकी परिवर्तन भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। डिजिटल दुनिया में कई बुजुर्ग स्वयं को असहज महसूस करते हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवार के सदस्य साथ रहते हुए भी एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ,आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा भी बुजुर्गों के जीवन को प्रभावित करती हैं। कई बार वे अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पाते और भीतर ही भीतर अकेलेपन का अनुभव करते हैं।

बुजुर्गों का सम्मान क्यों आवश्यक है?

बुजुर्गों का सम्मान केवल हमारी संस्कृति की परंपरा नहीं,बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान है। जो समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, वह अपने इतिहास, संस्कृति और मूल्यों का सम्मान करता है। बुजुर्गों का सम्मान करने से परिवार में सकारात्मक वातावरण बनता है। उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उनकी उपस्थिति हमें धैर्य,विनम्रता और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है।

सम्मान केवल शब्दों से नहीं,बल्कि व्यवहार से प्रकट होता है। उनके साथ समय बिताना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उन्हें निर्णयों में शामिल करना सच्चे सम्मान के प्रतीक हैं।

बदलती सोच की आवश्यकता

आज आवश्यकता है कि हम बुजुर्गों को बोझ नहीं,बल्कि संपत्ति समझें। हमें उनके अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए और उन्हें समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में देखना चाहिए। विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और परिवारों को मिलकर ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जिसमें बुजुर्गों का सम्मान स्वाभाविक रूप से हो। युवाओं को यह समझाना आवश्यक है कि आज के बुजुर्ग ही कल उनका भविष्य हैं।

यदि हम अपने बच्चों को बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाएँगे,तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे प्रति वही व्यवहार करेंगी। यह सम्मान और संवेदना की वह श्रृंखला है जो समाज को मानवीय बनाती है।बुजुर्ग वास्तव में घर की नींव हैं। वे परिवार के इतिहास, संस्कृति, अनुभव और मूल्यों के जीवंत स्रोत हैं। उनकी उपस्थिति घर को केवल एक मकान नहीं, बल्कि एक परिवार बनाती है। उनके अनुभव दिशा देते हैं, उनके संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन को समृद्ध बनाता है।

आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और रिश्तों में दूरियाँ बढ़ रही हैं, तब बुजुर्गों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमें उनके प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और मानवता की पहचान है।

याद रखिए,जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है,वहाँ सुख, शांति और संस्कारों का वास होता है। वास्तव में, बुजुर्ग ही वह मजबूत नींव हैं, जिन पर परिवार,समाज और राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य खड़ा होता है।

समय के दस्तावेज

राजेन्द्र लाहिरी,पामगढ़,छत्तीसगढ़

शब्द कभी केवल शब्द नहीं होते,
वे समय के दस्तावेज होते हैं,
जो लिखे जाते हैं
सदियों की चुप्पियों के बीच,
और पढ़े जाते हैं
आने वाली पीढ़ियों के प्रश्नों में।
जो सहा गया,
यदि वह लिखा नहीं गया,
तो इतिहास अक्सर
झूठ के पक्ष में खड़ा दिखता है।
सच की पीड़ा
कागज़ पर उतरना चाहती है,
ताकि आने वाला समय जाने
कि हम केवल दर्शक नहीं थे।
कितनी बार देखा हमने
अधिकारों को बिकते हुए,
विचारों को झुकते हुए,
और सच को
सिक्कों के नीचे दबते हुए।
मगर हर दौर में
कुछ कलमें बची रहीं,
जो झुकी नहीं,बिकी नहीं,
बस समय के सामने
आईना बनकर खड़ी रहीं।
ये दस्तावेज बताते हैं
कि अन्याय नया नहीं होता,
बस चेहरे बदलते रहते हैं।
कभी जाति के नाम पर,
कभी धर्म के नाम पर,
कभी सत्ता के मद में डूबकर
मनुष्य मनुष्य को तोड़ता रहता है।
पर समय भी गवाह है–
हर अँधेरे के विरुद्ध
एक दीप अवश्य जला है,
हर चुप्पी के विरुद्ध
एक स्वर अवश्य उठा है।
और जब भी इतिहास ने करवट ली,
उन स्वरों ने ही
भविष्य का रास्ता गढ़ा है।
इसलिए लिखो,
कि तुम्हारे शब्द
केवल तुम्हारे न रहें,
वे बनें समाज की स्मृति,
संघर्ष की विरासत,
और आने वाले कल के लिए
समय के जीवित दस्तावेज।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

रामलला के पैसे की चोरी: आस्था पर घात,डगमगाया विश्वास

अजय कुमार
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर से दान पात्र में चोरी की घटना ने एक साथ कई मोर्चों पर हलचल मचा दी है। करोड़ों रामभक्तों की आस्था को इस घटना ने गहरी ठेस पहुँचाई है तो उनका यह विश्वास भी टूट गया कि रामलला के मंदिर में ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं सकता है,लेकिन इससे भी बड़ी चोट तब लगी, जब इस धार्मिक मसले को राजनीति की चाशनी में लपेटकर परोसा जाने लगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लपक लिया और भारतीय जनता पार्टी की हिन्दूवादी राजनीति पर निशाना साधने में ज़रा भी देर नहीं की। यह सवाल अपनी जगह वाजिब है कि जिस मंदिर के दर्शन के लिये अखिलेश यादव आज तक नहीं गये, उस मंदिर के दान पात्र से हुई चोरी पर उनकी तड़प और चिंता कितनी वास्तविक है और कितनी दिखावटी। जो नेता रामलला के दर्शन से परहेज़ करते रहे,वे अचानक मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन के पहरेदार बन बैठे हैं। इसमें सच्चाई कम,सियासी गणित ज़्यादा दिखता है। सपा की इस सियासत से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिये 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या रामलला के मंदिर पहुँच रहे हैं, जहाँ वह पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझेंगे।

उधर,अखिलेश यादव की मंशा साफ है। वे भाजपा की हिन्दुत्व की छवि को खंड-खंड करना चाहते हैं। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था। यह मंदिर केवल ईंट-पत्थर का ढाँचा नहीं,बल्कि भाजपा की राजनीतिक पहचान का आधार-स्तंभ है। जब उसी मंदिर में चोरी होती है,तो यह भाजपा के लिये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि उसकी हिन्दुत्व की साख पर सीधा प्रहार बन जाता है। अखिलेश यादव इस कमजोर कड़ी को पकड़कर हिन्दू मतदाताओं के मन में यह संदेश डालना चाहते हैं कि भाजपा का हिन्दुत्व केवल चुनावी नारा है, व्यवहार में नहीं। इसके पीछे एक और सोचा-समझा राजनीतिक लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में हिन्दू मतदाता कभी एकजुट नहीं रहे। उच्च जातियों, पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच की खाई

को समाजवादी पार्टी हमेशा अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करती रही है। यदि अखिलेश इस घटना के माध्यम से हिन्दुओं के किसी तबके में यह धारणा बनाने में सफल हो जाते हैं कि भाजपा की सरकार में राम के घर में भी सुरक्षा नहीं, तो यह उनके लिये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक फायदा होगा।

लेकिन इस पूरे प्रसंग में असली सवाल यह है कि यह नौबत आई क्यों? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की भूमिका यहाँ बेहद अहम है। यदि वे इस घटना की जानकारी मिलते ही इसका खुलासा सार्वजनिक रूप से कर देते और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की बात करते,तो विपक्ष के पास आरोप लगाने की गुंजाइश ही नहीं बचती। जो घटना खुद उजागर की जाये,उस पर राजनीति करना कठिन होता है। लेकिन जब घटना को दबाने की कोशिश होती है और बाद में वह बाहर आती है,तो वह कहीं अधिक विस्फोटक बन जाती है। चंपत राय की यह अदूरदर्शिता महँगी पड़ी। इसी चूक ने अखिलेश को एक ऐसा हथियार थमा दिया, जिसे वे बार-बार भाँज सकते हैं। सपा की मंशा को भाँपकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है। यह कदम ज़रूरी था,लेकिन राजनीतिक नुकसान तो हो चुका था। जब तक जांच का आदेश आया,तब तक यह मुद्दा सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर आग की तरह फैल चुका था। मोदी और योगी दोनों की सरकारें इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिखीं,जो आमतौर पर सत्ता पक्ष के लिये ठीक संकेत नहीं माना जाता।

उधर,सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बयानबाज़ी में भी अतिरंजना है। वे ऐसी बातें भी इस घटना से जोड़ रहे हैं, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में यह स्वाभाविक भी है,लेकिन इससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। जो नेता कभी मंदिर के दर्शन नहीं करते,उनका मंदिर प्रेम अचानक चुनावी मौसम में जागता दिखे, तो जनता उसे पहचानती है। लाख टके का सवाल यह भी है कि यह मुद्दा क्या 2027 तक जीवित रह सकता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और राम जन्मभूमि न्यास इसे किस तरह संभालते हैं। यदि जांच में देरी हुई, दोषी पकड़ में नहीं आये,या मंदिर प्रशासन में कोई बड़ी खामी सामने आई,तो अखिलेश इसे जिंदा रखने में सफल होंगे। लेकिन यदि शीघ्र कार्रवाई हुई, दोषियों को सजा मिली और मंदिर प्रशासन में सुधार दिखा,तो यह मसला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। राजनीति में वही मुद्दे टिकते हैं,जिन्हें सत्ता पक्ष की लापरवाही ताज़ा रखती है।

लब्बोलुआब यह है कि रामलला का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का केन्द्र है। इस मंदिर से जुड़ी हर घटना, चाहे वह चोरी हो या कोई और विवाद, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रंग ले लेती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मंदिर के निर्माण से लाखों लोगों की भावनाएँ जुड़ी हैं, वह अब राजनीतिक शतरंज की बिसात बन रहा है। अखिलेश यादव इस बिसात पर चाल चल रहे हैं और भाजपा खुद की भूलों के कारण मुश्किल स्थिति में है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि राम मंदिर प्रबंधन को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाया जाये। चोरी की घटना से जो सबक मिला है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिये। मंदिर की सुरक्षा और प्रशासन में खामियाँ न केवल आस्था को आहत करती हैं,बल्कि विरोधियों को राजनीति करने का अवसर भी देती हैं। आस्था की रक्षा और प्रशासन की पारदर्शिता ही वह ढाल है,जो सियासत के तीरों को बेअसर कर सकती है।

योग,वैश्विक धरोहर और आधुनिक जीवन का आधार

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह
सहज,हरदा,मध्य प्रदेश

भारत की पावन धरा पर जन्मी योग की परंपरा मानव सभ्यता के इतिहास जितनी ही प्राचीन और गौरवशाली है। इसका आरंभ आदियोगी भगवान शिव से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों से लेकर वैदिक काल के ऋग्वेद और उपनिषदों में इसके बीज साफ दिखाई देते हैं। कालांतर में महाभारत और भगवद्गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने इसे कर्म, ज्ञान और भक्ति के व्यावहारिक मार्ग के रूप में स्थापित किया। इसके पश्चात, महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र की रचना कर अष्टांग योग के रूप में इसे एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित जीवन पद्धति का रूप दिया।

मध्यकाल में हठयोग के रूप में विकसित होती हुई यह विधा आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद और मनीषियों के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर गूंजी। अंततः भारत के ही पुरजोर प्रयासों से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे पूरी दुनिया द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया।आज के इस अति व्यस्त, तनावपूर्ण और गतिहीन आधुनिक दौर में योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं,बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। यह एक ओर जहाँ आसन और प्राणायाम के माध्यम से रीढ़ को लचीला, फेफड़ों को मजबूत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को तीव्र करता है, वहीं मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित भी करता है। दूसरी ओर, ध्यान और धारणा के जरिए यह मानसिक भटकाव को रोकता है, तनाव का स्तर कम करता है और एकाग्रता बढ़ाकर आंतरिक शांति प्रदान करता है। इसीलिए, इसे किसी भी धार्मिक चश्मे से परे एक निवारक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में हर व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना चाहिए,ताकि बिना किसी महंगे उपकरण के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर एक स्वस्थ,अनुशासित व सामंजस्यपूर्ण जीवन जिया जा सके और स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ा जा सके।

दिखावे की दानवीरता

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर,बिहार

आज-कल दिखावे की दानवीरता पर हर रोज सम्मान बाँट रहा है। काम से ज्यादा सम्मान की चिंता हो गई है। शायद वो समय चला गया जब लोग कहते थे कि कर्म करो,फल की चिन्ता मत करो तभी तो लोग आज कर्म से ज्यादा फल की चिन्ता करते हैं। एक समय था जब दान चुपके से होता था, सेवा निस्वार्थ भाव से होता है। अब तो दान का मतलब ही बदल गया है,सेवा का मतलब कैमरा, बैनर,माला,फोटो,अखबार की कटिंग हो गई। गरीब को 1 किलो चावल दिया और 100 फोटो खींच ली। मकसद पेट भरना नहीं, फेसबुक पर फोटो भरना रह गया और साथ ही दानवीरता के नाम पर सम्मान पाना हो गया है। जब एक समाज सेवी का सम्मान ही मकसद बन जाए तो दानवीरता / समाज सेवा भी व्यापार बन जाता है। स्टेज पर 10 मिनट का भाषण, गले में माला, हाथ में मोमेंटो। उसके बाद वही व्यक्ति मुड़कर उस गरीब को नहीं देखता जिसकी फोटो वायरल हुई थी ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं,ये आज की हकीकत है।

नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी,लेकिन सवाल बरकरार...

- सुपरमैन रंजीत गुप्ता की टीम ने फिर पकड़े 80 इंजेक्शन,पर हर बार सप्लायर तक पहुंचकर क्यों रुक जाती है जांच?
- 50 से ज्यादा प्रकरण,सैकड़ों गिरफ्तारियां और हजारों इंजेक्शन जब्त...फिर भी सरगुजा में नशे का नेटवर्क क्यों नहीं टूट रहा?

-संवाददाता-

अंबिकापुर,19 जून 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए लुंड्रा क्षेत्र से दो कथित नशे के सप्लायरों को 80 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। विभाग इसे बड़ी सफलता बता रहा है,लेकिन लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है...आखिर नशे की सप्लाई की जड़ तक जांच कब पहुंचेगी? सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए रवि घासी निवासी झेराडीह और किशुन राम उर्फ बबलू ठाकुर निवासी गढ़वीरा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 40 नग REXOGESIC और 40 नग AVIL इंजेक्शन बरामद किए गए। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया,जहां से जेल भेजने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई निश्चित रूप से विभाग की सक्रियता दिखाती है,लेकिन इसके साथ ही पिछले कई मामलों की तरह फिर वही सवाल सामने खड़ा हो गया है– क्या कार्रवाई केवल स्थानीय सप्लायरों तक ही सीमित रह जाएगी या इस बार पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा?

कार्रवाई पर कार्रवाई... फिर भी क्यों नहीं थम रहा कारोबार?

आबकारी विभाग के अनुसार पिछले एक वर्ष में नशीली दवाइयों के खिलाफ 50 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कई आरोपी गिरफ्तार हुए, बड़ी मात्रा में इंजेक्शन जब्त हुए और लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

लेकिन आंकड़ों के दूसरी तरफ एक कड़वा सवाल भी है...

- यदि कार्रवाई इतनी बड़ी संख्या में हो रही है तो फिर नशीले इंजेक्शन बाजार तक पहुंच कैसे रहे हैं?
- हर कुछ दिनों बाद नई खेप पकड़ी जा रही है। नए चेहरे सामने आ रहे हैं। और पुराने सवाल फिर खड़े हो रहे हैं।

क्या केवल छोटे विक्रेताओं और कैरियरों पर कार्रवाई से पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता है?

वाहिद से मोशीम और अब लुंड्रा तक...जांच की दिशा पर सवाल

हाल ही में वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसके कथित सप्लायर मोशीम अंसारी तक आबकारी टीम पहुंची थी। मोशीम के पास से 400 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे।

अब लुंड्रा क्षेत्र से दो और कथित सप्लायर पकड़े गए हैं।

लगातार कार्रवाई यह बताती है कि क्षेत्र में नेटवर्क सक्रिय है।

लेकिन सवाल यह है कि इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी वह मुख्य सप्लाई चैन क्यों सामने नहीं आ रही,जहां से बड़ी मात्रा में इंजेक्शन पहुंच रहे हैं?

गढ़वा कनेक्शन पर फिर उठे सवाल

सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता ने खुद बताया था कि मोशीम अंसारी को नशीले इंजेक्शन गढ़वा क्षेत्र के सप्लायरों से मिलते थे और वहां तक पहुंचने में विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने संसाधनों की कमी, साइबर सेल नहीं होने, सीमित बल और अन्य तकनीकी सुविधाओं के अभाव की बात कही।

यहीं से सवाल उठता है...

- जब सप्लाई का स्रोत सामने है तो वहां तक पहुंचने के लिए स्थायी रणनीति क्यों नहीं बन पा रही?
- क्या झारखंड पुलिस के साथ नियमित संयुक्त अभियान चलाया गया?
- क्या अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच शुरू हुई?
- क्या बड़े सप्लायरों तक पहुंचने के लिए कोई विशेष टीम गठित की गई?

जज्बा...बनाम संसाधन...असली चुनौती यही?

सुपरमैन रंजीत गुप्ता का कहना है कि विभाग के पास सीमित संसाधन हैं,लेकिन नशे के खिलाफ लड़ाई का जज्बा है। यह बात विभागीय कर्मचारियों के प्रयास को दर्शाती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए केवल जज्बा पर्याप्त नहीं होता।

इसके लिए चाहिए...

- तकनीकी जांच
- साइबर मॉनिटरिंग
- अंतरराज्यीय समन्वय
- आर्थिक जांच
- सप्लाई चैन की निगरानी

यदि यह सभी कड़ियां नहीं जुड़तीं तो कार्रवाई के बाद भी नेटवर्क नए रास्ते तलाश लेता है।

बैच नंबर खोल सकता है पूरा नेटवर्क

जब्त इंजेक्शनों के बैच नंबर पूरे मामले की अहम कड़ी हो सकते हैं। इनसे पता लगाया जा सकता है–

किस कंपनी ने बनाया?
किस स्टॉकिस्ट को भेजा?
किस मेडिकल चैनल से बाहर आया?
कहां से अवैध बाजार तक पहुंचा?

लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बैच नंबरों की विस्तृत जांच कर बड़े सप्लायरों और संबंधित संस्थानों तक पहुंच बनाई जा रही है?

ड्रग विभाग की भूमिका पर भी नजर...

नशीले इंजेक्शन आखिर किसी न किसी वैध दवा आपूर्ति चैन से निकलकर अवैध बाजार में पहुंचते हैं। ऐसे में केवल आबकारी विभाग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। औषधि प्रशासन विभाग को भी यह जांच करनी होगी कि...क्या किसी मेडिकल दुकान या स्टॉकिस्ट की भूमिका है? क्या रिकॉर्ड में गड़बड़ी है?,क्या लाइसेंसधारी संस्थानों से गलत तरीके से बिक्री हुई?

जनता के सवाल

- 50 से अधिक मामलों के बाद भी नशे का नेटवर्क क्यों सक्रिय है?
- बड़े सप्लायर और मास्टरमाइंड तक जांच कब पहुंचेगी?
- गढ़वा से आने वाली सप्लाई लाइन कब टूटेगी?
- क्या वित्तीय लेन-देन की जांच होगी?
- क्या केवल गिरफ्तारियां होंगी या पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई होगी?

क्योंकि सवाल यह नहीं है कि कितने इंजेक्शन पकड़े गए।

सवाल यह है कि...

इतनी कार्रवाई के बाद भी नशे का कारोबार चला कौन रहा है?

सरगुजा की जनता अब केवल गिरफ्तारी नहीं,बल्कि पूरे नेटवर्क के पर्दाफाश का इंतजार कर रही है।

डीजल-खाद संकट पर फूटा किसानों का गुस्सा

एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

काला बाजारी,खाद संकट और पेट्रोल पंपों की मनमानी के खिलाफ तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन...

-संवाददाता-

प्रतापपुर,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को डीजल,खाद और उर्वरक की उपलब्धता में आ रही गंभीर परेशानियों को लेकर प्रतापपुर तहसील परिसर में किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किसान नेताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीण किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

किसानों का कहना है कि प्रतापपुर विकासखंड के जरही,सोनगरा,खड़गवां,धोन्धा,रामपुर,भैसामुंडा, पोड़मोड़ और प्रतापपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप तो हैं,लेकिन ग्रामीण अंचलों से उनकी दूरी औसतन 20 किलोमीटर तक है। इसके बावजूद किसानों को जरीकन (डिब्बे) में डीजल देने से मना किया जा रहा है। ट्रैक्टर लेकर पहुंचने पर भी मात्र एक हजार रुपये का डीजल दिया जा रहा है,जिससे खेती-किसानी का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि खरीफ फसल की तैयारी शुरू हो चुकी है,खेतों की जुताई,बीड़ा निर्माण और सिंचाई का कार्य तेजी से किया जाना है,लेकिन डीजल की अनुपलब्धता के कारण किसान भारी संकट से गुजर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कृषि यंत्र और हस्तचालित मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें पेट्रोल पंप तक ले जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद किसानों को राहत नहीं दी जा रही है।

खाद और उर्वरक की किल्लत पर भी भड़के किसान

धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सहकारी समितियों में खाद और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। किसानों ने कहा कि उर्वरक के लिए परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाए तथा जिला सहकारी बैंक में जमा चेक राशि का एक ही दिन में खाते में अंतरण कर किसानों को नगद निकासी की सुविधा दी जाए।

काला बाजारी रोकने की मांग...

किसानों ने निजी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कई व्यापारी स्टॉक छिपाकर खाद की काला बाजारी कर रहे हैं और किसानों को महंगे दामों पर उर्वरक बेच रहे हैं। किसानों ने मांग की कि निजी दुकानों के स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन कराया जाए, अधिकतम खुदरा मूल्य और कंपनी के बिलों की जांच की जाए तथा दोषी पाए जाने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

50 लीटर डीजल देने की प्रमुख मांग...

किसानों ने प्रशासन से मांग की कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक किसान को जुताई एवं सिंचाई कार्य के लिए जरीकन में कम से कम 50 लीटर डीजल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था किसानों के लिए अव्यावहारिक और नुकसानदायक साबित हो रही है।

मांगें नहीं मानी गईं तो होगा उग्र आंदोलन

किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा,जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। धरना-प्रदर्शन में मुख्य रूप से विद्यासागर आयाम,नवीन जायसवाल,त्रिभुवन सिंह,जगत लाल आयाम,सुरेश चक्रधारी,शिवकुमार जायसवाल,नेहरू पटेल,विनोद नेताम,राजू सिंह आयाम,कलमेश राजवाड़े,प्यारेलाल नागवंशी,रामजनम यादव, जानसाय,विजय कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते डीजल, खाद और बीज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो खरीफ सीजन प्रभावित होगा और इसका सीधा असर किसानों की आजीविका पर पड़ेगा।

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य ने अस्पतालों का किया निरीक्षण,कर्मचारी मिले अनुपस्थित

-संवाददाता-

सूरजपुर,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉ. अनिल शुक्ला ने गुरुवार को सूरजपुर जिले के भैयाथान,ओडग़ी और बिहारपुर-चांदनी स्थित स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में साफ-सफाई, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं,जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान तीनों संस्थानों में कुल 13 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

संयुक्त संचालक ने सबसे पहले मातृ एवं शिशु अस्पताल भैयाथान का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचना एवं प्रचार सामग्री (आईईसी) और अधिक लगाने के निर्देश दिए। मरीजों के परिजनों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया।

निरीक्षण के दौरान पिछले माह हुए 23 संस्थागत प्रसव की समीक्षा करते हुए उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही खंड चिकित्सा अधिकारी और खंड कार्यक्रम प्रबंधक को विकासखंड के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण करने के लिए कहा। खंड चिकित्सा अधिकारी को उपस्थिति पंजी का नियमित निरीक्षण एवं संधारण सुनिश्चित करने तथा बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

दोपहर में संयुक्त संचालक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओडग़ी का निरीक्षण किया। यहां पुरुष और महिला मरीजों के लिए अलग-अलग वार्ड निर्धारित करने, अस्पताल में साफ-सफाई बनाए रखने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आईईसी सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा ऋतु को देखते हुए मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त भंडारण रखने और सर्पदंश की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान दंत चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूजा मिश्रा एवं लैब टेक्नीशियन प्रियम चतुर्वेदी अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित मिले। इसके अलावा कुल नौ अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। शाम को संयुक्त संचालक ने दूरस्थ क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर-चांदनी का निरीक्षण किया। यहां अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। उन्होंने संस्था प्रभारी को नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि नए अस्पताल भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। संयुक्त संचालक ने सीजीएमएससी से समन्वय स्थापित कर भवन का शीघ्र हैंडओवर कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अस्पताल में चार अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित मिले। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

27 करोड़ की सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर नजर,विधायक प्रबोध मिंज ने अधिकारियों को लगाई फटकार

-संवाददाता-

लखनपुर,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

लूँड्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रबोध मिंज ने नावापारा से कुन्नी पहुंच मार्ग का औचक निरीक्षण किया। लगभग 13 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 27 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सड़क में कई कमियां पाए जाने पर विधायक प्रबोध मिंज ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सुधार कार्य शुरू करने और निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। विधायक ने स्पष्ट कहा कि जनता के हित में बनाई जा रही सड़क किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता पूर्ण कार्य ही स्वीकार किया जाएगा। इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष रवि महंत, सरपंच प्रमोद सिंह, खेमराज सिंह, विधायक प्रतिनिधि राकेश साहू, प्रवीण यादव, जमुना प्रसाद, सुरेश सिंह, मंत्री सारथी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक प्रबोध मिंज ने स्थानीय जनसमस्याओं पर भी चर्चा की और पार्टी कार्यकर्ताओं को जनसेवा में और अधिक सक्रिय रहने की अपील की। गुणवत्ता पूर्ण सड़क बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

अनधिकृत अनुपस्थिति एवं विभागीय जांच के उपरांत भृत्य की सेवा समाप्त

-संवाददाता-

अंबिकापुर,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ दिनेश कुमार झा द्वारा जारी आदेशानुसार कार्यालय में पदस्थ भृत्य श्री रामकुमार राजवाड़े की सेवाएं अनधिकृत अनुपस्थिति एवं विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के उपरांत समाप्त कर दी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रामकुमार राजवाड़े दिनांक 09 फरवरी 2022 से बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार कार्यालय से अनुपस्थित थे। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न पत्रों एवं कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा कार्य पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया। श्री राजवाड़े द्वारा वर्ष 2023 में प्रस्तुत आवेदन में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए पुनः कार्यभार ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। इसके उपरांत जिला ग्रंथालय, अम्बिकापुर में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति भी प्रदान की गई, किन्तु उन्होंने वहां भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया तथा पुनः अनुपस्थित रहे।

असुरक्षित घोषित, खरीद-बिक्री एवं भंडारण बंद करने की अपील

-संवाददाता-

अंबिकापुर,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

आम जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ Bheem ka Mango (Packed) Green Colour (Mango Ice Candy) को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर द्वारा परीक्षण उपरांत असुरक्षित (Unsafe) घोषित किया गया है। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों से अपील की जाती है कि उक्त खाद्य पदार्थ का क्रय एवं सेवन न करें। साथ ही सभी खाद्य विक्रेताओं, थोक एवं फुटकर व्यापारियों से अनुरोध है कि इस उत्पाद का क्रय, विक्रय एवं भंडारण तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, ताकि अनजाने में भी इसके विक्रय की संभावना न रहे। संबंधित विक्रेता एवं व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपलब्ध स्टॉक को अन्य खाद्य पदार्थों से पृथक सुरक्षित रूप से संधारित करें, जिससे उत्पाद के निर्माता कंपनी को वापस करने की कार्यवाही सुगमतापूर्वक की जा सके। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

अच्छे अंक के साथ अच्छा नागरिक बनना भी जरूरी,तभी समाज और देश को आप पर होगा गर्व:कलेक्टर अजीत वसंत

होली क्रॉस स्कूल में सीबीएसई टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान,96 बच्चों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर बढ़ाया विद्यालय का गौरव

-संवाददाता-

अंबिकापुर,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

सफलता केवल अच्छे अंक हासिल करने तक सीमित नहीं है,बल्कि जीवन में एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना सबसे जरूरी है। जब आपका योगदान समाज और देश के हित में होगा,तभी सभी को आप पर गर्व होगा। यह बात कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत वसंत (आईएएस) ने होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बिकापुर में आयोजित मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में कही।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ उनके माता-पिता भी मौजूद रहे। बच्चों को सम्मानित होते देख अभिभावकों और शिक्षकों में खुशी और गर्व का माहौल रहा। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम गौरवशाली रहा। कक्षा 12वीं के 18 और कक्षा 10वीं के 78 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। सभी मेधावी विद्यार्थियों को कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

कलेक्टर बोले...अंक नहीं,मेहनत और सोच तय करती है भविष्य

विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आज सम्मानित होने वाले बच्चों की मेहनत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों को इस बार सम्मान नहीं मिला, वे निराश न हों। यह अंतिम अवसर नहीं है,लगातार मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोपें, बल्कि उनकी रुचि और क्षमता को समझकर उनका मार्गदर्शन करें। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान हासिल कर एक अच्छा नागरिक बनना है।

प्राचार्य ने कहा...सफलता के पीछे मेहनत और सहयोग अहम

विद्यालय की प्राचार्य डॉ. सिस्टर जेस्सी थेक्कन ने कहा कि यह सम्मान विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सफलता के सफर में अभिभावकों और शिक्षकों का सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि परीक्षा के अंक किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करते। लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच से हर विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है।

सांस्कृतिक माहौल में हुआ आयोजन

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और स्वागत गीत से हुई। विद्यालय के बैगपाइपर बैंड ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका रिम्शा श्रीवास्तव, नीलम पोद्दार, जस्सी अब्राहम और आशीष अग्रवाल ने किया। आभार प्रदर्शन शिक्षिका रितु सोनी ने किया। समारोह को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कलेक्टर रोक्तिमा यादव पहुंचीं स्कूल, ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाया गणित,

शिक्षकों को सौंपी बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी

औचक निरीक्षण में शैक्षणिक गुणवत्ता का लिया जायजा, अनुपस्थित विद्यार्थियों पर जताई नाराजगी

-रवि सिंह-

कोरिया,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने शुक्रवार को बैकुंठपुर विकासखंड के विभिन्न शासकीय प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया, उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन किया तथा शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ब्लैकबोर्ड पर लिखकर समझाया गणित

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने स्वयं ब्लैकबोर्ड संभाला और विद्यार्थियों को गणित के प्रश्न लिखकर सरल एवं रोचक तरीके से समझाया,उन्होंने बच्चों से सवाल पूछकर उनकी समझ का परीक्षण किया और उन्हें नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया,कलेक्टर ने शिक्षकों से कहा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि एवं सीखने की ललक विकसित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है,इसके लिए केवल पाठ्य-पुस्तकों तक सीमित न रहकर नवाचारी एवं रोचक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

मनसुख विद्यालय में अनुपस्थित विद्यार्थियों पर जताई नाराजगी

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनसुख के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली,बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और प्राचार्य सहित शिक्षकों से जवाब मांगा,उन्होंने कहा कि विद्यालय खुलने के बाद भी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होना गंभीर विषय है,पालकों से संपर्क कर बच्चों को विद्यालय लाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए,इस लापरवाही पर उन्होंने प्राचार्य को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

बच्चों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका

कलेक्टर ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने तक सीमित नहीं है,बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को दिशा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को दसवीं और बारहवीं कक्षा के बाद करियर विकल्पों, विषय चयन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में भी मार्गदर्शन दें,जिस समर्पण के साथ वे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर,अधिकारी या प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, उसी भावना से विद्यालय के प्रत्येक बच्चे के भविष्य को संवारने का प्रयास करें।

बीईओ और डीईओ को दिया नियमित निरीक्षण का निर्देश

कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने,शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करने तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बच्चे मिट्टी की तरह, सही मार्गदर्शन से मिलेगा बेहतर आकार

प्राथमिक शाला बंजारीडांड में कलेक्टर ने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की स्थिति का अवलोकन किया,उन्होंने एक-एक विद्यार्थी से बातचीत कर उनकी सीखने की क्षमता और शैक्षणिक स्तर का आकलन किया,अध्ययन स्तर संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने प्रधान पाठक को फटकार लगाई और कहा कि बच्चे मिट्टी के समान होते हैं, जिन्हें उचित मार्गदर्शन और परिश्रम से बेहतर आकार दिया जा सकता है,उन्होंने बच्चों की दक्षता और क्षमता विकास के लिए विशेष प्रयास करने तथा कक्षा अनुसार बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हर शनिवार होगी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

कलेक्टर ने शिक्षकों को प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है,जिसे पहचानकर निखारना आवश्यक है,उन्होंने कहा कि शिक्षकों का दायित्व केवल नौकरी करना नहीं,बल्कि बच्चों की नींव मजबूत करना,उनमें आत्मविश्वास विकसित करना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है।

पाठ्यपुस्तकों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश

कलेक्टर ने सभी विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन कार्य तत्काल प्रारंभ करने तथा सभी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए,जिन विद्यार्थियों को नई पुस्तकें नहीं मिली हैं,उन्हें अस्थायी रूप से पुरानी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए कहा गया ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

पालकों से की विशेष अपील

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती यादव ने पालकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें और उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें।

विद्यार्थियों से पूछा सपना, बच्चों ने बताए अपने लक्ष्य

कलेक्टर ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में भी चर्चा की, कई विद्यार्थियों ने डॉक्टर,शिक्षक, पुलिस अधिकारी और सैनिक बनने की इच्छा व्यक्त की, इस पर कलेक्टर ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोई भी सपना कठिन परिश्रम,अनुशासन और निरंतर अध्ययन के बल पर ही साकार किया जा सकता है तथा इसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

नवप्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत

विद्यालय निरीक्षण के दौरान कक्षा छठवीं और नवमीं में प्रवेश लेने वाले नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर और मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया गया, कलेक्टर ने बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए शुभकामनाएं दीं और मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी।

मध्याह्न भोजन और साफ-सफाई व्यवस्था की भी जांच

कलेक्टर ने विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना का भी निरीक्षण किया,उन्होंने रसोईघर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता, सब्जियों, दाल, चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री का परीक्षण किया,उन्होंने शिक्षकों को निर्देशित किया कि बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा भोजन से पूर्व हाथ धोने की आदत विकसित की जाए, साथ ही विद्यालय परिसर, शौचालय और पेयजल व्यवस्था की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

सत्ता उनकी, चर्चा हमारीः अध्यक्ष भाजपा का,लेकिन उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने मारी बाजी

एक वोट ने बदल दिया पूरा राजनीतिक गणित,अंशुल गोयल बने नगर पंचायत शिवनंदनपुर के प्रथम उपाध्यक्ष, भाजपा के प्रशांत अग्रवाल को मिले 7 वोट,कांग्रेस के अंशुल गोयल को 8 मत, एक वोट हुआ निरस्त

-संवाददाता-

सूरजपुर/शिवनंदनपुर,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

नविन नगर पंचायत शिवनंदनपुर के पहले चुनाव में उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम ने स्थानीय राजनीति में नई बहस और नए सवाल खड़े कर दिए हैं,भले ही नगर पंचायत अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में गया हो, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अंशुल गोयल की जीत ने राजनीतिक चर्चा का केंद्र बदल दिया है। अब पूरे क्षेत्र में एक ही सवाल गूंज रहा है–आखिर वह एक वोट किसका था जो निरस्त हो गया और जिसने पूरे चुनावी गणित को बदलकर रख दिया? उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित अंशुल गोयल को 8 वोट प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रशांत अग्रवाल को 7 मत मिले। वहीं एक वोट निरस्त हो गया, परिणाम सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि यदि वह वोट निरस्त नहीं होता तो क्या तस्वीर कुछ और होती? क्या मुकाबला बराबरी पर पहुंचता? क्या भाजपा उपाध्यक्ष पद भी जीत जाती? या फिर परिणाम फिर भी कांग्रेस के पक्ष में जाता? इन सवालों के जवाब भले अभी न मिले हों, लेकिन चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य वही एक निरस्त वोट बन गया है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद जीतने की उम्मीद में थी भाजपा

नगर पंचायत अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में जाने के बाद यह लगभग माना जा रहा था कि उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा आसानी से कब्जा कर लेगी, सत्ता पक्ष होने का लाभ, संगठन की ताकत और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए भाजपा दोनों पदों पर जीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मतदान के बाद आए परिणाम ने सारी गणनाएं बदल दीं, कांग्रेस भले ही अध्यक्ष पद हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उपाध्यक्ष पद जीतकर उसने यह संदेश दे दिया कि स्थानीय राजनीति में उसकी मौजूदगी अभी भी मजबूत है और उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

आखिर किसका वोट हुआ निरस्त?

उपाध्यक्ष चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा अब उस एक वोट को लेकर है जो निरस्त घोषित किया गया,राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं,कोई इसे मतदान प्रक्रिया में हुई तकनीकी गलती बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक जल्दबाजी का परिणाम मान रहा है,स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि यदि वह वोट वैध माना जाता तो परिणाम का स्वरूप बदल सकता था,हालांकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत संपन्न हुई और परिणाम घोषित कर दिया गया,लेकिन निरस्त मत अब पूरे चुनाव का सबसे चर्चित विषय बन चुका है।

सत्ता के सामने जनमत की ताकत

शिवनंदनपुर के इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि लोकतंत्र में केवल सत्ता और संसाधन ही सब कुछ नहीं होते, कई बार जनप्रतिनिधियों की सामूहिक इच्छा, संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक एकजुटता सत्ता के प्रभाव पर भारी पड़ जाती है, कांग्रेस ने पूरे चुनाव के दौरान अपने पार्षदों और समर्थकों को एकजुट बनाए रखा, संगठनात्मक अनुशासन और राजनीतिक समन्वय का परिणाम अंशुल गोयल की जीत के रूप में सामने आया,यही कारण है कि इस जीत को केवल एक पद की जीत नहीं बल्कि विपक्ष की प्रभावशाली उपस्थिति के रूप में देखा जा रहा है।

अंशुल गोयल की जीत का राजनीतिक संदेश...

नगर पंचायत शिवनंदनपुर के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए अंशुल गोयल की जीत को स्थानीय जनता की अपेक्षाओं और राजनीतिक विश्वास से भी जोड़कर देखा जा रहा है, यह परिणाम बताता है कि स्थानीय निकायों में राजनीति केवल सत्ता के आधार पर नहीं चलती, बल्कि जनप्रतिनिधियों का आपसी विश्वास और संगठनात्मक मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है,कांग्रेस खेमे में इस जीत को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह परिणाम बताता है कि जनता और जनप्रतिनिधि केवल सत्ता के साथ खड़े होने के आधार पर निर्णय नहीं लेते,बल्कि स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता और जनसरोकारों को भी महत्व देते हैं।

सत्ता भाजपा की...लेकिन चर्चा कांग्रेस की...

नगर पंचायत शिवनंदनपुर में अध्यक्ष पद भाजपा के पास है,लेकिन उपाध्यक्ष चुनाव के बाद राजनीतिक चर्चा कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूम रही है, एक वोट के अंतर से मिली जीत और एक वोट के निरस्त होने ने इस चुनाव को सामान्य चुनाव से अलग बना दिया है,फिलहाल नगर पंचायत की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह एक वोट किसका था जिसने पूरे चुनाव का गणित बदल दिया,जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता,तब तक शिवनंदनपुर का यह उपाध्यक्ष चुनाव स्थानीय राजनीति की सबसे चर्चित कहानी बना रहेगा।

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका फिर हुई साबित

शिवनंदनपुर के परिणाम ने यह भी साबित किया है कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की ताकत होता है,जब विपक्ष प्रभावी होता है तो सत्ता पक्ष की जवाबदेही बढ़ती है और लोकतांत्रिक संतुलन मजबूत होता है,अंशुल गोयल की जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं,बल्कि उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत मानी जा रही है जिसमें अंतिम फैसला सत्ता नहीं बल्कि मत और जनमत करते हैं।

भाजपा के लिए आत्ममंथन का अवसर

उपाध्यक्ष पद पर मिली हार भाजपा के लिए भी आत्ममंथन का विषय बन गई है,अध्यक्ष पद जीतने के बावजूद उपाध्यक्ष पद हाथ से निकल जाना यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रणनीति या समन्वय में कमी रही है,अब भाजपा के भीतर भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं कि सत्ता पक्ष होने के बावजूद उपाध्यक्ष पद उसके खाते में नहीं आ सका।

FORMAT OF TENDER NOTICE FOR PUBLICATION ON NEWS PAPERS

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH,
WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
WATER RESOURCES DIVISION NO.1AMBIKAPUR

e-Procurement Tender Notice

Main Portal: http://egeprocurement.gov.in
WRD Portal: http://wrd.cgeprocurement.gov.in

[FIRST-CALL]
Corrigendum

No. 01 /SAC/2026-27 Date 15-06-2026

The following partial modifications are made. In the tender invited vide N.I.T. No. 01/SAC/2026- 27 Dated 02-06-2026 as per details given below. Whose "G" No. 262701221 Date. 05-06-2026 (1) Date of Bid Start may be read as 15.06.2026 instead of 09.06.2026
(2) Date of Bid due of tender may be read as 30-06-2026 (17:30 hours) in stead of dated 23-06-2026 (17:30 hours)
(3) Date of Bid Open start may be read as 01-07-2026 (11:30 hours) in stead of dated 24-06-2026 (11:30 hours)
Note:- According Key Dats has been changed Detailed key dates can be viewed from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in On sub portal of Water Resources Department: https://wrd.cgprocurement.gov.in and all other terms and conditions will be remain and unchanged.

Executive Engineer
Water Resources Division No.1
Ambikapur
For-Chief Engineer
Hasdeo Ganga Basin, W.R. Deptt.
Ambikapur (C.G.)

G.N.-262701518/5

न्यायालय तहसीलदार लुण्ड्रा(धौरपुर)
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम सरईडीह को सुचित किया जाता है कि न्यायालय कलेक्टर, जिला सरगुजा अम्बिकापुर के पत्र क्र0/616/वाचक /2025 अम्बिकापुर दिनांक 29/10/2025 के तहत् आवेदक मुंगालाल आ0 पनमेश्वर, निवासी ग्राम सरईडीह, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर), जिला सरगुजा (छ0ग0) द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सरईडीह, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित ख0नं0 9/1 रकबा 0.525 हे0 एवं ख0नं0 448/2 रकबा 0.793 हे0 भूमि में से रकबा 0. 392 हे0 भूमि को अनावेदक उमेश यादव आ0 छद्दू यादव, निवासी ग्राम पटोरा, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) के पास बिक्री करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जो जांच हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति पेश करना हो तो वह दिनांक 30/6/ 2026 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 10/6/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
लुण्ड्रा(धौरपुर),सरगुजा

तीन मौतें...दर्जनों सवाल

नौगई हत्याकांड में न्याय से पहले जबाब तलाश रहा पूरा जिला

सीबीआई जांच,सीडीआर खंगालने और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज,पुलिस,राजनीति और प्रशासन पर उठ रहे सवाल

पूर्व विधायक पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच, क्षेत्रीय विधायक की चुप्पी चर्चा में, सामाजिक संगठन आंदोलन की तैयारी में

नौगई की जलती रात के बाद उठते सवाल, न्याय की मांग,जांच पर संदेह और सियासत में सन्नाटा

नौगई तिहरा हत्याकांडः तीन चिताओं की राख में दबे सवाल, न्याय की तलाश में भटकता परिवार और संदेहों के घेरे में व्यवस्था

नौगई हत्याकांडः आरोपियों से ज्यादा व्यवस्था कटघरे में, न्याय की राह अब भी अधूरी

क्या कानून सबके लिए बराबर है?

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उभरकर सामने आया है कि क्या कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो रहा है,विपक्ष का आरोप है कि यदि किसी अन्य मामले में बुलडोजर और त्वरित कार्रवाई की मांग की जाती है तो इस मामले में भी वैसी ही तत्परता दिखनी चाहिए,दूसरी ओर विधि विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कार्रवाई का आधार केवल कानून और साक्ष्य होने चाहिए,न कि राजनीतिक दबाव या जनभावनाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायालय,पुलिस और जांच एजेंसियां ही अपराध तय करती हैं, न कि सोशल मीडिया।

सोनहत थाना प्रभारी की भूमिका को लेकर भी चर्चा

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर थाना प्रभारी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्षेत्र में चर्चा है कि कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण था और घटना वाले दिन स्थिति और अधिक गंभीर हो चुकी थी,कुछ लोगों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की सक्रियता अपेक्षित स्तर की नहीं दिखाई दी,वहीं जनचर्चाओं में यह मांग भी उठ रही है कि मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण संपर्कों और संचार माध्यमों की तकनीकी जांच हो ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या भ्रम को दूर किया जा सके, हालांकि इन चर्चाओं और आरोपों की अभी तक किसी आधिकारिक जांच से पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन जनता का मानना है कि निष्पक्ष जांच ही इन सवालों का उत्तर दे सकती है।

सीडीआर जांच की मांग आखिर क्यों?

पीड़ित परिवार और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देकर सीडीआर जांच की मांग की है,उनका कहना है कि घटना से पहले और बाद के मोबाइल संपर्कों की जांच से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं,लोगों का मानना है कि यदि तकनीकी जांच निष्पक्ष तरीके से होती है तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, कौन-कौन लोग संपर्क में थे और क्या किसी स्तर पर लापरवाही या चूक हुई थी।

सामाजिक संगठनों का बढ़ता दबाव

घटना के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है, कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच और शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है, हालांकि सामाजिक संगठनों ने अब तक शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी है,लेकिन लगातार बढ़ते जनदबाव को प्रशासन नजरअंदाज नहीं कर सकता।

न्याय केवल होना नहीं चाहिए,दिखना भी चाहिए...

लोकतंत्र में न्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही माना जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए, नौगई तिहरा हत्याकांड में यही सबसे बड़ी चुनौती है, यदि जांच निष्पक्ष होगी, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों का उपयोग होगा तथा जांच की प्रगति पारदर्शी तरीके से सामने आएगी तो जनता का विश्वास मजबूत होगा,लेकिन यदि देरी हुई,अस्पष्टता बनी रही या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हावी रहे तो संदेह और अविश्वास और गहरा सकता है।

अब पूरे जिले की नजर जांच पर...

नौगई की तीन चिताएं बुझ चुकी हैं,लेकिन उनसे उठे सवाल अब भी धधक रहे हैं,पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, समाज सच्चाई जानना चाहता है, विपक्ष जवाब मांग रहा है और प्रशासन पर निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी है,आज सबसे बड़ी आवश्यकता किसी राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचने की नहीं, बल्कि तथ्यों तक पहुंचने की है। दोषी चाहे कोई भी हो,कानून के सामने जवाबदेह होना चाहिए और यदि किसी पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं तो जांच से उन्हें भी स्पष्ट रूप से खारिज होना चाहिए, नौगई तिहरा हत्याकांड अब केवल तीन हत्याओं का मामला नहीं रह गया है, यह कानून के शासन,प्रशासनिक जवाबदेही,राजनीतिक संवेदनशीलता और न्यायिक निष्पक्षता की परीक्षा बन चुका है,आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है,यही तय करेगा कि लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिलता है या वे और गहरे होते चले जाते हैं।

4 मुख्य आरोपियों गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मुख्य आरोपियों (सत्यप्रकाश, विशाल, अक्षय और महेंद्र त्रिपाठी) को गिरफ्तार कर लिया है,रेत उत्खनन विवाद को लेकर भाजपा नेता भरत सिंह और उनके साथियों की गाड़ी को घेरकर जिंदा फूंकने और हमला करने वाले इस जघन्य अपराध के अन्य फरार 5 आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, इस बर्बर वारदात के बाद पूरे इलाके में उपजे भारी तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य घटनास्थल और खेरवार घाट के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, सभा या हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत,19 जून 2026 (घटती-घटना)।

सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में घटित तिहरे हत्याकांड ने केवल तीन लोगों की जान नहीं ली, बल्कि पूरे जिले के सामने कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सतर्कता,राजनीतिक जवाबदेही और न्यायिक निष्पक्षता को लेकर कई गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं,तीन लोगों को कथित रूप से जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार देने की घटना की भयावहता ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, घटना के कई दिन बाद भी गांव में पसरा सन्नाटा, पीड़ित परिवारों की आंखों में दिखता दर्द और समाज के भीतर बढ़ती बेचैनी इस बात का संकेत दे रही है कि मामला केवल एक आपराधिक घटना भर नहीं रह गया है।

घटना के बाद जिस प्रकार पूरे प्रदेश में प्रतिक्रिया देखने को मिली,उसने इस मामले को राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है,कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों पर इस घटना को लेकर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है,विपक्षी नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए सवाल उठाए हैं कि आखिर ऐसा कौन सा माहौल तैयार हो गया है जिसमें रेत कारोबार से जुड़े विवादों का अंत अदालत,प्रशासन और कानून से नहीं बल्कि आग और मौत से होने लगा है,हालांकि दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति,राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत होगा, इसलिए इस पूरे मामले में सबसे अधिक आवश्यकता निष्पक्ष,स्वतंत्र और तथ्यों पर आधारित जांच की है।

घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल,क्या यह अचानक हुआ अपराध था या सुनियोजित वारदात?

नौगई की घटना को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या यह केवल क्षणिक आवेश का परिणाम था या फिर पहले से तैयार की गई योजना के तहत अंजाम दिया गया अपराध,जिस तरीके से तीन लोगों की मौत हुई, उसने लोगों के मन में अनेक आशंकाओं को जन्म दिया है,ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि घटना के पहले दोनों पक्षों के बीच तनाव था और स्थानीय स्तर पर इसकी जानकारी मौजूद थी तो फिर समय रहते रोकथाम क्यों नहीं हुई? यदि विवाद बढ़ रहा था तो क्या पर्याप्त निगरानी रखी गई थी? क्या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जांच एजेंसियों को देना होगा।

पुलिस को पहले से जानकारी थी तो वारदात क्यों नहीं रुकी?

घटना के बाद पुलिस की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, लोगों का कहना है कि यदि पुलिस को दोनों पक्षों के बीच विवाद और तनाव की जानकारी थी,तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई,यदि संभावित खतरे की आशंका थी तो अतिरिक्त पुलिस बल,निगरानी और शांति व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास क्यों नहीं किए गए,जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि या तो खतरे का सही आकलन नहीं किया गया या फिर हालात को गंभीरता से नहीं लिया गया। दोनों ही स्थितियां कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय मानी जा रही हैं।

पीड़ित परिवार की खामोशी बहुत कुछ कह रही है...

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे मार्मिक पक्ष पीड़ित परिवारों का व्यवहार रहा है,न तो उन्होंने किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन किया और न ही अंतिम संस्कार के समय कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न की,लेकिन उनकी खामोशी के भीतर गहरा दर्द और व्यवस्था के प्रति अविश्वास साफ दिखाई देता है, स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवारों को शायद यह महसूस हो रहा है कि केवल मांग करने से न्याय नहीं मिलेगा,इसलिए उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास का संकेत भी है और व्यवस्था के प्रति चिंता का भी।

सीबीआई जांच और सीडीआर जांच की मांग क्यों हो रही है?

पीड़ित परिवार और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है,ज्ञापन में कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है,मांग करने वालों का तर्क है कि यदि घटना से पहले और बाद के मोबाइल संपर्कों की तकनीकी जांच की जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं, उनका मानना है कि इससे उन सभी चर्चाओं और आशंकाओं का समाधान भी होगा जो वर्तमान में क्षेत्र में फैल रही हैं, विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य जांच को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए यदि जांच एजेंसियां आवश्यक समझें तो ऐसे सभी पहलुओं की वैज्ञानिक जांच की जा सकती है।

पूर्व विधायक पहुंचे,वर्तमान विधायक की अनुपस्थिति चर्चा में...

घटना के बाद भरतपुर-सोनहत क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरो घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की,वहीं क्षेत्रीय विधायक रेणुका सिंह की सार्वजनिक सक्रियता को लेकर विपक्ष और सोशल मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं,यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी जनप्रतिनिधि की अनुपस्थिति या उपस्थिति को अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं माना जा सकता,लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में जनता अपने प्रतिनिधियों से संवेदनशील प्रतिक्रिया की अपेक्षा अवश्य करती है, यही कारण है कि क्षेत्र में इस विषय को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है।

सोशल मीडिया ने बढ़ाया राजनीतिक तापमान

घटना के बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां सामने आई हैं, कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया मंच से लेकर स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक अनेक लोगों ने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, कुछ पोस्टों में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में कथित माफिया तंत्र मजबूत हो रहा है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, वहीं सत्तापक्ष के समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद बता रहे हैं, सच्चाई क्या है, इसका निर्धारण केवल जांच और न्यायिक प्रक्रिया ही कर सकती है।

मृतकों का आपराधिक रिकॉर्ड गिनाकर क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच रही है?

घटना के बाद पुलिस द्वारा मृतकों और आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किए जाने से भी नई बहस शुरू हो गई है,पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि पुलिस को पहले से यह जानकारी थी कि दोनों पक्षों के बीच विवाद है और कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं,तो फिर बड़ी घटना होने से पहले रोकथाम क्यों नहीं की गई,लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड होना उसकी हत्या का औचित्य नहीं बन सकता, कानून व्यवस्था का उद्देश्य अपराध रोकना और अपराधियों को कानून के दायरे में लाना है, न कि हत्या के बाद पुरानी फाइलें खोलकर घटना की गंभीरता को कम करना।

क्या पुलिस ने आरोपियों को फरार होने का मौका दिया, या यह केवल संयोग था?

घटना के बाद सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि मुख्य आरोपी कानून की पकड़ से दूर कैसे चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस को घटना की जानकारी समय पर मिल गई थी और आरोपियों की पहचान स्पष्ट थी,तो फिर तत्काल घेराबंदी और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यही कारण है कि अब क्षेत्र में यह मांग तेज हो रही है कि घटना से पहले और बाद की पूरी पुलिस कार्रवाई सार्वजनिक की जाए,लोगों का कहना है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि आरोपियों को भागने का अवसर कैसे मिला,तब तक संदेह समाप्त नहीं होंगे, ग्रामीणों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि जब आरोपियों की पहचान स्पष्ट थी,तब तत्काल घेराबंदी और गिरफ्तारी की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी,इसी कारण क्षेत्र में यह संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं न कहीं गंभीर चूक हुई है,जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है,घटना के बाद सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मुख्य आरोपी अब तक पूरी तरह कानून के शिकंजे में क्यों नहीं आ सके,क्षेत्र में लोगों के बीच यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि यदि पुलिस को घटना की जानकारी समय पर मिल गई थी तो फिर आरोपियों को भागने का अवसर कैसे मिला? जनता के मन में उठ रहे इन सवालों का उत्तर केवल तथ्यों और जांच से ही मिल सकता है, फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी,लेकिन यह भी सच है कि आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने से जनसंदेह बढ़ता है और अफवाहों को बल मिलता है, हालांकि इन सभी सवालों का अंतिम उत्तर केवल निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है।

CMYK

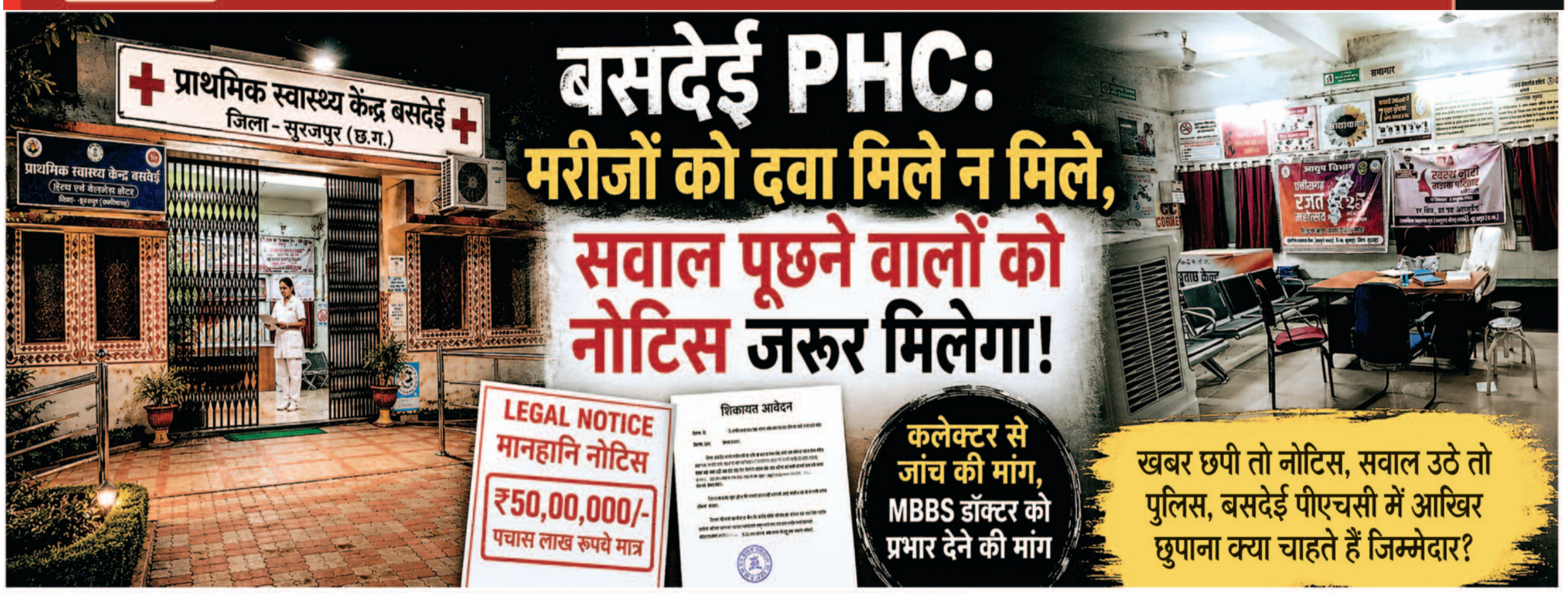

बसदेई पीएचसी : व्यवस्था पर सवाल उठाओ तो नोटिस,नोटिस के बाद भी बोलो तो पुलिस शिकायत! व्यवस्था पर सवाल उठाओ और कटघरे में पहुंच जाओ! बसदेई पीएचसी विवाद ने खड़े किए बड़े प्रश्न अस्पताल की बदहाली पर नहीं,खबरों पर कार्रवाई क्यों? बसदेई पीएचसी फिर विवादों में क्या बसदेई पीएचसी की प्रभारी सीएमएचओ से भी ऊपर? सवालों से ज्यादा सक्रिय दिखा नोटिस तंत्र बसदेई पीएचसी: इलाज कम,विवाद ज्यादा,अब कलेक्टर तक पहुंची शिकायत...

-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,19 जून 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले का बसदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि सवालों,विवादों,शिकायतों,नोटिसों और प्रशासनिक संरक्षण की चर्चाओं का केंद्र बन चुका है, पिछले कई महीनों से अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं,कभी अस्पताल में आरएमए प्रभारी व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, कभी एमबीबीएस डॉक्टरों की भूमिका को लेकर बहस हुई,कभी नाइट ड्यूटी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति चर्चा में रही, तो कभी मरीजों के इलाज के बजाय रेफर किए जाने की शिकायतें सामने आईं,लेकिन इन सवालों का जवाब व्यवस्था सुधार के रूप में कम और नोटिसों तथा शिकायतों के रूप में ज्यादा दिखाई दिया।

अब मामला उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां बसदेई के ग्रामीणों ने सीधे कलेक्टर सूरजपुर को लिखित शिकायत देकर स्वास्थ्य केंद्र की संपूर्ण प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर दी है, शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र को लेकर लगातार विवाद, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट, प्रशासनिक समन्वय की कमी और मरीजों की बढ़ती परेशानियों की जांच की जाए तथा अस्पताल का प्रभार एमबीबीएस चिकित्सक को सौंपने पर विचार किया जाए।

खबरें छपती रहीं,सवाल बढ़ते रहे...

बसदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर प्रकाशित खबरों में लगातार यह सवाल उठता रहा कि जब अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ हैं तो फिर अस्पताल संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर विवाद क्यों है? ग्रामीणों ने कई बार आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज से ज्यादा रेफर की व्यवस्था दिखाई देती है,रात के समय डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल उठे। ग्रामीणों का कहना रहा कि ड्यूटी रोस्टर कागजों में तो मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में कई बार मरीजों को डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर करना आम बात बन चुकी है,इसी दौरान अस्पताल परिसर में प्रभारी के लिए आवंटित सरकारी क्वार्टर पर वर्षों से ताला लटकने और मुख्यालय में निवास न करने जैसे आरोप भी चर्चा में रहे।

50 लाख का मानहानि नोटिस और फिर पुलिस शिकायत

अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली खबरों के जवाब में 50 लाख रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया,लेकिन नोटिस के बाद भी जब खबरें प्रकाशित होती रहीं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठते रहे तो मामला पुलिस तक पहुंच गया,यहीं से पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया,अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि खबरें गलत थीं तो स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की? यदि अस्पताल की व्यवस्था आदर्श थी तो ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को शिकायत क्यों दी गई? और यदि शिकायतें निराधार हैं तो जांच कर सच्चाई सामने लाने के बजाय नोटिस और पुलिस शिकायतों का सहारा क्यों लिया जा रहा है?

क्या सीएमएचओ से भी ऊपर है बसदेई पीएचसी की प्रभारी ?

पूरा मामला अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है,जिले के स्वास्थ्य विभाग का मुखिया सीएमएचओ होता है,लेकिन बसदेई पीएचसी को लेकर उठे विवादों में अब तक ऐसा कोई बड़ा कदम सामने नहीं आया जिससे यह लगे कि व्यवस्था सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता है,इसके उलट खबरें प्रकाशित होने के बाद नोटिस,फिर पुलिस शिकायत और अब पूछताछ की प्रक्रिया ने कई लोगों को यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बसदेई पीएचसी की प्रभारी को किस स्तर का संरक्षण प्राप्त है? ग्रामीणों का कहना है कि यदि अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें गलत हैं तो विभाग जांच कर सच्चाई सामने लाए, लेकिन यदि शिकायतें सही हैं तो सुधारात्मक कार्रवाई करे। सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा करना समाधान नहीं हो सकता।

कलेक्टर तक पहुंची शिकायत ने बढ़ाई मुश्किलें...

अब तक जो बातें केवल खबरों और चर्चाओं तक सीमित थीं,वे अब आधिकारिक शिकायत का हिस्सा बन चुकी हैं,कलेक्टर को दिए गए आवेदन में स्वास्थ्य केंद्र की संपूर्ण व्यवस्था की जांच,मरीजों और ग्रामीणों की शिकायतों का सत्यापन,स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन और एमबीबीएस चिकित्सकों की भूमिका की समीक्षा की मांग की गई है,शिकायत में यह भी कहा गया है कि जहां एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं,वहां अस्पताल का प्रशासनिक प्रभार उन्हें सौंपा जाना अधिक उचित होगा ताकि चिकित्सा और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों सुनिश्चित हो सकें।

व्यवस्था पर सवाल या सवाल करने वालों पर कार्रवाई ?

बसदेई पीएचसी विवाद अब एक मूल प्रश्न पर आकर खड़ा हो गया है,क्या प्राथमिकता अस्पताल की व्यवस्था सुधारना है या फिर व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को जवाब देना? यदि मरीजों को पर्याप्त सुविधा मिल रही है,यदि नाइट ड्यूटी सुचारू है,यदि प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है,यदि अस्पताल में कोई विवाद नहीं है, तो फिर लगातार शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? और यदि शिकायतें वास्तविक हैं, तो कार्रवाई अस्पताल की व्यवस्था पर क्यों नहीं दिखाई दे रही?

अब निगाहें प्रशासन पर...

कलेक्टर तक पहुंची शिकायत के बाद अब पूरा मामला जिला प्रशासन के पाले में है, जांच होती है तो कई सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं-अस्पताल का वास्तविक संचालन कौन कर रहा है? नाइट ड्यूटी की वास्तविक स्थिति क्या है? एमबीबीएस डॉक्टरों की भूमिका क्या है? मरीजों को रेफर क्यों किया जाता है? और आखिर बसदेई पीएचसी विवाद का मूल कारण क्या है? फिलहाल इतना जरूर है कि बसदेई पीएचसी अब केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था पर उठते सवालों,नोटिसों, शिकायतों और जवाबदेही की बहस के लिए जाना जाने लगा है। और जब किसी अस्पताल की पहचान इलाज से ज्यादा विवादों से बनने लगे,तो यह केवल उस अस्पताल नहीं बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय माना जाता है।

मोदी सरकार के 12 वर्ष: विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रबुद्धजनों से किया संवाद

चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में जनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं समाजसेवियों का किया सम्मान

-संवाददाता-
चिरमिरी,19 जून 2026
(घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्धजनों, समाजसेवियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया,इस दौरान उन्होंने चिरमिरी क्षेत्र में विभिन्न लोगों के निवास पर पहुंचकर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया तथा केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। 12 वर्षों में भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए: विधायक-संवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास,सुशासन,आधारभूत संरचना, डिजिटल तकनीक,स्वास्थ्य,शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं,उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं ने देश को नई दिशा देने का कार्य किया है तथा भारत आज विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है,उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य किया है।

जनकल्याणकारी योजनाओं ने बदली करोड़ों लोगों की जिंदगी

विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है, वहीं उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया है,उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता के प्रति जनजागरण पैदा किया है, जबकि डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन और सेवाओं को आम नागरिकों की पहुंच तक पहुंचाया है,किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रबुद्धजनों से मांगे सुझाव,जनभागीदारी को बताया लोकतंत्र की ताकत

कार्यक्रम के दौरान विधायक ने उपस्थित प्रबुद्धजनों से देश के विकास, सामाजिक समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर सुझाव भी आमंत्रित किए,उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता की सहभागिता है और नागरिकों के विचार एवं सुझाव शासन की नीतियों को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,प्रबुद्धजनों ने भी देश के विकास, सामाजिक समरसता,युवाओं के भविष्य,शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपने विचार साझा किए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से बढ़ रहा देश-

विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है,विज्ञान,तकनीक, रक्षा,अंतरिक्ष, उद्योग और आर्थिक क्षेत्र में देश लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उन्होंने कहा कि भारत अब केवल विकासशील राष्ट्र नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक मजबूत और निर्णायक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में उभर रहा है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में जनभागीदारी,सुशासन और विकास की इसी भावना के साथ भारत विश्व के अग्रणी देशों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

मनेंद्रगढ़ में भी होगा प्रबुद्धजन संवाद

विधायक ने बताया कि चिरमिरी के बाद इसी क्रम में मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर उनका सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उन्होंने कहा कि जनसंपर्क और संवाद के माध्यम से लोगों तक सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है।

बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित

इस अवसर पर जिला महामंत्री द्वारिका प्रसाद जायसवाल,श्रीपत राय,बबलू महराज,राजकुमार बधावन, प्रमोद सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक,समाजसेवी, वरिष्ठजन एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा पर चर्चा करते हुए राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।

CMYK

भाग्यश्री की जगह मैंने प्यार किया में सलमान खान के अपोजिट कास्ट होने वाली थीं उपासना सिंह,इस वजह से हुईं रिजेक्ट

फिल्म मैंने प्यार किया में भाग्यश्री की जगह उपासना सिंह को कास्ट किया जाना था। लेकिन सूरज बड़जात्या के पिता ने उन्हें इस कारण रिजेक्ट कर दिया गया था।
सलमान खान और भाग्यश्री अभिनीत फिल्म मैंने प्यार किया साल 1989 में रिलीज हुई थी। सूरज बड़जात्या ने इसे डायरेक्ट किया था और ये जबरदस्त हिट साबित हुई थी। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि भाग्यश्री की भूमिका निभाने के लिए पहले अभिनेत्री उपासना सिंह को ये रोल ऑफर हुआ था। हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया।

मुंबई आकर दिया था ऑडिशन

इसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए सूरज बड़जात्या के पिता राज कुमार बड़जात्या से भी संपर्क किया। उपासना सिंह ने गलाटा इंडिया के साथ पुरानी यादें ताजा करते हुए मैंने प्यार किया के अपने ऑडिशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा,उस समय मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी और मेरी आंटी चेंबूर में रहती थीं। मैं हमेशा कहती थी कि मुझे हीरोइन बनना है। इसलिए, जब भी मैं मुंबई आती थी, तो इन सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलती थी।

बचपन से थिएटर

कर रही थीं उपासना

उन्होंने आगे कहा, तो एक बार जब मैं मुंबई आई तो मैं गुप्ता जी (जो सूरज बड़जात्या का काम संभालते हैं) से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि राजश्री मैंने प्यार किया नाम की एक फिल्म बना रही है और वह मुझे सूरज बड़जात्या से मिलवाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बचपन से ही थिएटर कर रही हूं और मुझे एक्टिंग में दिलचस्पी है। सूरज बड़जात्या ने कोई प्रॉपर ऑडिशन नहीं लिया, बस मुझसे तीन-चार डायलॉग बोलने को कहा। मैं उन्हें पसंद आई और उन्होंने गुप्ता जी से कहा कि उनकी तरफ से मेरा सिलेक्शन हो गया है।

सूरज बड़जात्य के पिता ने किया रिजेक्ट

सूरज चाहते थे कि उपासना उनके पिता से भी मिलें। इसके बाद गुप्ता जी ने उपासना को फोन करके बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया है। उपासना ने उनके पिता से भी मुलाकात कर ली थी और चंडीगढ़ वापस चली आईं। एक्ट्रेस ने आगे कहा-लेकिन मुझे कभी कोई फोन नहीं आया। फिर फिल्म बनी। मैंने काफी समय तक फिल्म नहीं देखी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि हीरोइन मैं थी और फिल्म मेरे बिना बन गई। मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे चुना गया था क्योंकि यह मुझे बहुत बुरा लगा।

सलमान खान को मालूम थी ये बात

उपासना ने बताया कि इसके बाद उन्होंने बरजात्या के साथ मैं प्रेम की दीवानी हूं की शूटिंग की थी जब खुद सूरज बड़जात्या के पिता ने ये बात सबके सामने बोली। राज कुमार बड़जात्या ने कहा कि फिल्म में पहले भाग्यश्री की जगह उन्हें कास्ट किया जाना था लेकिन बाद में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इतना सुनकर उपासना भड़क गई और बोलीं कि फिर उन्होंने उन्हें कास्ट क्यों नहीं किया? इस पर राजकुमार ने उपासना को बताया कि वो सलमान खान से ज्यादा लंबी थीं इस वजह से उन्हें रिजेक्ट किया गया था। उपासना ने बताया कि सलमान को ये बात मालूम थी।
सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित, मैंने प्यार किया ने सलमान खान की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में आलोक नाथ,मोहनीश बहल, रीमा लागू,राजीव वर्मा,अजीत वचानी और लक्ष्मीकांत बेर्डे भी मुख्य भूमिकाओं में थे।

गुटर-गुटर गाने की लिरिसिस्ट को लेकर चर्चा

साल 1993 में रिलीज हुई अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दलाल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी,लेकिन फिल्म से ज्यादा उसके गानों ने लोगों का ध्यान खींचा था। फिल्म का संगीत उस दौर में बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके कई गीत आज भी श्रोताओं के बीच पसंद किए जाते हैं। हालांकि, फिल्म का एक गाना ऐसा भी था जिसने लोकप्रियता के साथ-साथ विवाद भी खड़ा कर दिया था। यह गीत रेडियो और सार्वजनिक मंचों पर खूब बजाया जाता था, लेकिन इसके बोलों को लेकर कई जगह आपत्ति जताई गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ रेडियो स्टेशनों ने इस गाने के प्रसारण पर रोक तक लगा दी थी। दिलचस्प बात यह थी कि जिस गीत को लेकर इतना विवाद हुआ,उसके बोल किसी पुरुष गीतकार ने नहीं बल्कि प्रसिद्ध गीतकार माया गोविंद ने लिखे थे। उस समय यह बात भी चर्चा का विषय बनी थी कि एक महिला गीतकार ने इतने बोल्ड और अलग अंदाज वाले गीत की रचना की थी। रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म का चर्चित गीत चोली के पीछे क्या है था,जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। गीत की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि यह उस दौर के सबसे चर्चित गानों में शामिल हो गया। हालांकि, इसके बोलों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस भी छिड़ गई थी। कई संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए विरोध दर्ज कराया था। विवादों के बावजूद गाने की लोकप्रियता कम नहीं हुई। संगीत प्रेमियों ने इसे हाथोंहाथ लिया और यह गीत लंबे समय तक चार्टबस्टर बना रहा। फिल्म के संगीत ने भी इसकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाई। आज, तीन दशक से अधिक समय बाद भी यह गीत और उससे जुड़ा विवाद बॉलीवुड इतिहास का एक चर्चित अध्याय माना जाता है। कई लोग इसे हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार और विवादित गीतों में गिनते हैं। कुल मिलाकर,दलाल का यह गाना सिर्फ अपनी धुन और लोकप्रियता के लिए ही नहीं,बल्कि उससे जुड़े विवाद और चर्चाओं के लिए भी याद किया जाता है।

मौसी ने बताया आखिरी पलों का दर्दनाक सच

कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन ने टीवी इंडस्ट्री और उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। 14 जून 2026 को मुंबई के नालासोपारा स्थित घर में उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद परिवार ने उस दिन की पूरी कहानी सामने रखी है। दिन भर सामान्य रहा माहौल परिवार के अनुसार उस दिन दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। खाना खाने के बाद संचिता की एक दोस्त भी घर आई थी और सभी ने साथ में भोजन किया। इसके बाद माता-पिता बाजार जाने लगे,लेकिन संचिता ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। संचिता ने अपनी छोटी बहन के साथ डांस क्लास जाने से भी मना कर दिया। बहन अकेली चली गई और संचिता घर पर ही रुक गईं। इसी दौरान वह घर में अकेली थीं। पिता ने कमरे में देखा दर्दनाक दृश्य करीब शाम 7:30 बजे जब माता-पिता लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिश के बाद दरवाजा खोला गया. अंदर पिता ने देखा कि संचिता पंखे से साड़ी के सहारे लटकी हुई थीं। फंदे से उतारने पर चल रही थीं सांसें मौसी के अनुसार जब उन्हें नीचे उतारा गया तो उनकी सांसें चल रही थीं। परिवार तुरंत अस्पताल लेकर गया,लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। काम के दबाव में थीं परेशान परिवार और दोस्तों के अनुसार संचिता हाल के दिनों में काम के दबाव में थीं। नए शो 'साजन घर' में अधिक काम और तनाव के कारण वह ठीक से आराम नहीं कर पा रही थीं।

बिल्ला के हिंसक किरदार में ऐसे डूबे रमनदीप यादव,खराब हुई मेंटल हेल्थ,सेट पर महिला एडीएस भी खाने लगी थीं खौफ!

रमनदीप यादव ने राख में खूंखार रज्जो का किरदार निभाते हुए मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया। हिंसक भूमिका के गहरे प्रभाव से बाहर आने में उन्हें काफी समय लगा, जिससे सेट पर भी अजीब माहौल बन गया था। एक डार्क या विलेन का किरदार निभाना काफी मुस्किल काम है। इसका एक एक्टर के मन पर भी कई बार गहरा असर पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ राख के रज्जो उर्फ रमनदीप यादव के साथ।

मेंटल हेल्थ पर पड़ा बुरा असर

राख की कहानी साल 1978 के चर्चित रंगा-बिल्ला केस पर आधारित है। रमनदीप सिंह ने फिल्म में कुख्यात बदमाश बिल्ला का किरदारा निभाया है। रमनदीप को पता था कि ये मुश्किल होगा लेकिन फिर भी वो इसके लिए राजी हो गए। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल और हिंसक किरदार को जीने के भारी बोझ ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। एक्टर को इससे बाहर आने में बहुत वक्त लगा। शूटिंग खत्म होने के बाद रमन को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ी। एनडीटीवी के साथ बातचीत में रमन ने बताया कि उनकी मेंटल हेल्थ काफी खराब हो गई थी। इस भयावह हिंसा के सीन्स अक्सर उनकी आंखों के सामने आ जाते थे।

सेट पर था अजीब सा माहौल : रमनदीप

बातचीत में एक्टर ने कहा- बहुत ज्यादा थका देने वाला था। मुझे अभी भी याद है, मैं एक कोने में अपना म्यूजिक लगा के बैठा रहता था, यहां तक कि जो मेरे एडीएस थे,वे महिला एडीएस थी,मैनें उन्हें बात करते हुए सुना। एक ने कहा, मुझसे रज्जो से बात ही नहीं करनी है, तुम जाके बात कर लो,तुम उसको सीन बता दो।वो मुझे जैसा दिखता है ना,मुझे बड़ा अजीब लगता है। तब मैंने बोला सो सॉरी लेकिन मैं जोन में था और मैं वो ब्रेक नहीं लेना चाहता था जो मैं रियल लाइफ में फील कर रहा था।

वापस रमन बनने के लिए की तगड़ी मेहनत

किरदार में घुसने के लिए रमन ने अपने घर का सेट अप भी बदला था। एक्टर ने कहा- रज्जो के साथ ऐसा हो रहा था मैं अपनी चीजें भूलने लगा था। मेरी अलमारी कहां है,कपड़े कहा हैं? मैं दो रंग के मोजे पहनने लगा था। वहीं इस किरदार से बाहर आने के लिए भी निखिल को बहुत मेहनत करनी पड़ी। शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने क्लीन शेव करवाई और अपने पुराने दोस्तों से मिलने पहुंचे ताकि असली रमनदीप से मिल सकें। राख अभी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इसमें अली फजल और सोनाली बेंद्रे भी अहम भूमिकाओं में हैं।

तारा सिंह और सकीना की वापसी की उम्मीदों पर फैंस उत्साहित

सनी देओल और अमीषा पटेल की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है। गदर और गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दमदार परफॉर्मेंस देने के बाद अब दोनों कलाकारों के तीसरी किस्त यानी गदर 3 में वापसी की संभावनाएं तेज हो गई हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इस बात को लेकर चर्चा बढ़ गई है कि मेकर्स एक बार फिर इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। गदर का पहला पार्ट साल 2001 में रिलीज हुआ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। उस समय फिल्म ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई थी। सनी देओल का तारा सिंह का किरदार और अमीषा पटेल का सकीना का रोल आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है।

इसके बाद लंबे अंतराल के बाद गदर 2 रिलीज हुई, जिसने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। इसकी सफलता के बाद ही गदर 3 को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, मेकर्स इस फ्रेंचाइजी की कहानी को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं,हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन फिल्म की लोकप्रियता और फैंस की डिमांड को देखते हुए तीसरे पार्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सनी देओल के एक्शन और दमदार डायलॉग्स ने हमेशा से ही इस फ्रेंचाइजी को खास बनाया है, वहीं अमीषा पटेल का किरदार कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अगर गदर 3 बनती है तो यह एक बार फिर बड़े स्तर पर बनाई जाएगी और इसमें पहले से भी ज्यादा भव्यता देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नए किरदारों को भी जोड़ा जा सकता है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपनी उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर तारा सिंह और सकीना की कहानी बड़े पर्दे पर देखने को मिले। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख या पुष्टि सामने नहीं आई है।

खेल समाचार

चेन्नई में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी वनडे शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा,जहां भारत की नजरें 3-0 से क्लीन स्वीप पर होंगी...

चेन्नई,19 जून 2026। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज को पहले ही 2-0 से अपने नाम कर चुकी भारतीय क्रिकेट टीम अब तीसरे और अंतिम मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शनिवार को चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। शुरुआती दोनों मैचों में एकतरफा प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया इस डेड-रबर मैच में कुछ खिलाड़ियों को परखना चाहेगी, जबकि अफगानिस्तान के सामने साख बचाने की चुनौती होगी।

यशस्वी जायसवाल के पास दावेदारी मजबूत करने का आखिरी मौका

इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर टिकी होंगी। सीरीज के पिछले मैच में जहां कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने शानदार शतक जड़कर टीम को जीत दिलाई थी,वहीं जायसवाल सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। आगामी इंग्लैंड सीरीज में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की संभावित वापसी होने वाली है, जिससे टीम का बल्लेबाजी क्रम बदल सकता है। ऐसे में जायसवाल के लिए खुद को प्लेइंग-11 की रेस में बनाए रखने के लिए चेन्नई में एक बड़ी और धमाकेदार पारी खेलना बेहद जरूरी होगा।

नंबर-6 पर केएल राहुल की नई भूमिका का होगा टेस्ट

मध्यक्रम में टीम इंडिया के अनुभवी खिलाड़ी केएल राहुल की भूमिका पर भी सबका खास फोकस रहेगा। टीम मैनेजमेंट उन्हें नंबर-6 पर एक फिनिशर के रूप में देख रहा है। राहुल से उम्मीद होगी कि वह आखिरी के ओवरों में आकर तेजी से रन बटोरें और इस नए रोल में खुद को पूरी तरह ढालकर टीम की ताकत बढ़ाएं।

चोट से उबरकर लौटे हर्षित राणा,नितीश रेड्डी चोटिल

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा घुटने की चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं और चेन्नई वनडे में उनकी प्लेइंग 11 में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी ओर, नितीश कुमार रेड्डी जांघ की इंजरी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण राणा को खेलने का सुनहरा अवसर मिलेगा। आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड के महत्वपूर्ण दौरों को देखते हुए टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता हर्षित राणा की फिटनेस और मैच फॉर्म का बारीकी से आकलन करना चाहेंगे।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारतः शुभमन गिल (कप्तान),रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर,ईशान किशन (विकेटकीपर), केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव,अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा।
अफगानिस्तानः हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान),रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर),इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अतल,अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी,राशिद खान, इकराम अलीखिल, फरीद अहमद मलिक, एएम गजनफर, बिलाल सामी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के बाद कनाडा-कतर मैच में बवाल

वैंकूवर,19 जून 2026। वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप बी मुकाबले के बाद कनाडा और कतर के खिलाड़ियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली,जो बाद में हाथापाई में बदल गई। इस मुकाबले में सह-मेजबान ने दो बार की एशियाई चैंपियन को 6-0 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की थी। मैच के दौरान जहां कनाडा का प्रदर्शन पूरी तरह हावी रहा,वहीं खेल के बाद हुई एक घटना ने पूरे मुकाबले को विवादों में घेर दिया। जानकारी के अनुसार,एक टैकल के बाद कनाडाई मिडफील्डरगंभीर रूप से घायल हो गए। टैकल के दौरान उनका पैर टूट गया,जिससे मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और स्टाफ स्तब्ध रह गए।
घटना के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही मिनटों में हाथापाई में बदल गई। सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। मैच के बाद का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच भी चिंता का माहौल बन गया। कनाडा के मुख्य कोचने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जीत की खुशी एक गंभीर चोट के कारण पूरी तरह फीकी पड़ गई। कोच के अनुसार,इस्माइल कोन की चोट टीम के लिए बड़ा झटका है और उनकी स्थिति पर मेडिकल टीम लगातार नजर रख रही है।
मैच के दौरान कनाडा ने आक्रामक शुरुआत की और पहले हाफ में ही कई गोल दागकर कतर की डिफेंस को पूरी तरह दबाव में ला दिया। दूसरे हाफ में भी कनाडा ने अपना दबदबा बनाए रखा और अंततः 6-0 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यह जीत टीम के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि यह वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिहाज से अहम मुकाबला था। हालांकि,मैच के बाद हुई घटना ने इस शानदार जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फुटबॉल विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं खेल भावना के खिलाफ हैं और इनसे खिलाड़ियों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा होती है। फिलहाल फुटबॉल अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट मांगी गई है। मेडिकल टीम इस्माइल कोन की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है, जबकि दोनों टीमों से अनुशासनात्मक रिपोर्ट भी तलब की जा सकती है। यह मुकाबला जहां स्कोरलाइन के लिहाज से कनाडा के लिए ऐतिहासिक रहा, वहीं मैदान के बाहर की घटना ने इसे विवादों और चिंता से जोड़ दिया है।

बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारत ए महिला टीम में किया बदलाव

चेन्नई,19 जून 2026। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए लेग-स्पिनर प्रेमा रावत को सीनियर नेशनल टीम में बुलाए जाने के बाद,बीसीसीआई महिला सिलेक्शन कमिटी ने शुक्रवार को इंग्लैंड ए के खिलाफ होने वाली बाइलेटरल सीरीज़ के लिए इंडिया ए स्क्वाड में कुछ अहम बदलावों की घोषणा की। ऑलराउंडर निकी प्रसाद को इंडिया ए टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है,जबकि ऑफ-स्पिनर मिन्नू मणि को वन-डे टीम में जगह दी गई है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा,महिला सिलेक्शन कमिटी ने इंग्लैंड ए के खिलाफ आगामी सीरीज़ के लिए इंडिया, स्क्वाड में ये बदलाव किए हैं: निकी प्रसाद को इंडिया ए टी 20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। मिन्नू मणि को इंडिया ए वन-डे स्क्वाड में शामिल किया गया है।शुरुआत में, निकी का नाम सिर्फ़ वन-डे स्क्वाड में था, जबकि मणि टी 20 टीम का हिस्सा थीं और प्रेमा दोनों व्हाइट-बॉल स्क्वाड में शामिल थीं। लेकिन,17 जून को नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान एंकल में चोट लगने के कारण श्रेयंका पाटिल के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने और श्रेयंका की जगह प्रेमा को मेन स्क्वाड में शामिल किए जाने के बाद, सिलेक्टर्स ने इंडिया ए स्क्वाड में खाली जगहों को भरने के लिए तेज़ी से कदम उठाए। अनुष्का शर्मा अपडेटेड टी 20 स्क्वाड की कप्तानी करेंगी और वृंदा दिनेश उनकी डिप्टी होंगी, जबकि अनुभवी हरलीन देओल वन-डे टीम की कप्तानी करेंगी, जिसमें उप-कप्तान प्रतिका रावल शामिल हैं। इंडिया ए के इंग्लैंड दौरे में 20 जून से शुरू होने वाले तीन टी 20 आई और उसके बाद 1 जुलाई से तीन वन-डे मैच खेले जाएंगे।

संविदा कर्मचारियों का तबादला भी वैध यह सरकार का अधिकार : हाईकोर्ट

बिलासपुर,19 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की पदस्थापना और तबादले को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि तबादला और पदस्थापना सरकारी सेवा का अभिन्न हिस्सा हैं। किसी कर्मचारी को किस स्थान पर पदस्थ किया जाना है, यह निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी का विशेषाधिकार है और केवल संविदा कर्मचारी होने के आधार पर स्थानांतरण आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभुदत्त गुरु की एकलपीठ ने की। स्वास्थ्य विभाग के एक संविदा कर्मचारी ने 6 मई 2026 को जारी अंतर-जिला स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि संविदा कर्मचारी होने के कारण उनके तबादले को निरस्त किया जाना चाहिए,लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई कर्मचारी स्थानांतरण आदेश को चुनौती देता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है या नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। केवल असंतोष या व्यक्तिगत असुविधा के आधार पर तबादला आदेश रद्द नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण और पदस्थापना प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है और न्यायालय सामान्य परिस्थितियों में इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती करना शासन का अधिकार है। अपने निर्णय में अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि स्थानांतरण सेवा का स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए केवल संविदा कर्मचारी होने का आधार स्थानांतरण आदेश को अवैध नहीं बनाता। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया हो, तब न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित होता है। यदि किसी आदेश में स्पष्ट कानूनी त्रुटि,नियमों का उल्लंघन या दुर्भावनापूर्ण मंशा दिखाई नहीं देती,तो अदालत को प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार के स्थानांतरण आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए तबादला आदेश को बरकरार रखा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी पहल : 'सुघ्घर छत्तीसगढ़'

अभियान से सुशासन का लाभ पहुंचेगा हर परिवार तक...

सीएम साय का नया मिशन...23 जिलों में योजनाओं की होगी हैंड-टू-हैंड डिलीवरी

रायपुर,19 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश के 23 जिलों में 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं के संतृप्तिकरण का व्यापक कार्यक्रम होगा,जिसके माध्यम से योजनाओं की पहुंच,प्रभावशीलता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार तक शासन की योजनाओं की प्रभावी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं संचालित करना नहीं,बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनके सकारात्मक परिणाम प्रत्येक परिवार के जीवन में दिखाई दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े,बल्कि शासन स्वयं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और उन्हें योजनाओं से जोड़े। 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' इसी सोच का विस्तार है।

'नियद नेल्लानार' की सफलता से प्रेरित नई पहल

वर्ष 2024 से बस्तर संभाग में संचालित 'नियद नेल्लानार' योजना ने शासन और जनता के बीच विश्वास का नया सेतु निर्मित किया है।अभिसरण आधारित सेवा प्रदाय के माध्यम से इस योजना ने दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में शासन की उपस्थिति को मजबूत किया तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की

पहुंच सुनिश्चित की। योजना की सफलता को देखते हुए इसे 'नियद नेल्लानार 2.0' के रूप में 10 जिलों तक विस्तारित किया गया। अब इसी सफल मॉडल को प्रदेश के शेष 23 जिलों में लागू करते हुए 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में संचालित होगा और ग्रामीण परिवारों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगा। 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान अंतर्गत रायपुर संभाग के रायपुर,बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी एवं महासमुंद जिले,बिलासपुर संभाग के बिलासपुर,कोरबा,जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती,गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले; दुर्ग संभाग के दुर्ग,बालोद, बेमेतरा,कबीरधाम (कवर्धा) एवं राजनांदगांव जिले तथा सरगुजा संभाग के सरगुजा,कोरिया,सूरजपुर,बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी विकसित करेगा अत्याधुनिक डिजिटल डैशबोर्ड : अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी द्वारा एक एकीकृत 'सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड' विकसित किया जाएगा। यह डैशबोर्ड राज्य, संभाग, जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर तक योजनाओं की प्रगति को रियल-टाइम में प्रस्तुत करेगा। डैशबोर्ड पर प्रत्येक योजना की संतृप्तिकरण स्थिति, शेष हितग्राहियों की संख्या तथा प्रगति का प्रतिशत उपलब्ध रहेगा।

तीन चरणों में होगा अभियान का संचालन : अभियान का क्रियान्वयन सुव्यवस्थित रूप से तीन चरणों में किया जाएगा।पहले चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण एवं डेटा मानचित्रण किया जाएगा। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी। दूसरे चरण में ग्राम, क्लस्टर एवं विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेजों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तीसरे चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अभियान के सफल संचालन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिला कलेक्टर जिला स्तरीय क्रियान्वयन के प्रमुख अधिकारी होंगे और आधारभूत सर्वेक्षण, शिविरों के आयोजन तथा संतृप्तिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। संभागायुक्त संभाग स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा करेंगे, जबकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति अभियान की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करेगी।

सुशासन से संतृप्ति की ओर

'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान का मूल उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साझा मंच पर लाकर पात्र हितग्राहियों तक उनका शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना है। 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण स्थापित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा, जिसमें योजनाओं की जानकारी, पात्रता, प्रगति और संतृप्तिकरण की स्थिति एकीकृत रूप से उपलब्ध होगी।

31 जनकल्याणकारी योजनाओं का होगा संतृप्तिकरण

अभियान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार,खाद्य सुरक्षा,स्वास्थ्य,शिक्षा,महिला सशक्तिकरण,कृषि, कौशल विकास तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं से जुड़ी 31 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, महतारी वंदन योजना, जन-धन योजना, कौशल विकास योजनाएं, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा, आधार कार्ड तथा विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के अवसर उपलब्ध कराना है।

स्मार्ट मीटर हटाने घर-घर जाकर समर्थन पत्र भरवाएगी कांग्रेस

बैज बोले...5 बार बढ़ाई गई बिजली दरें,भाजपा बोली...जनता कांग्रेस को नकार चुकी...

रायपुर,19 जून 2026। छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी ने तय किया है कि जुलाई में कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने के समर्थन में लोगों से समर्थन पत्र भरवाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि सरकार आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, जबकि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस ने इन सभी मुद्दों को लेकर आंदोलन का निर्णय लिया है। ऐसे में आगामी मानसून सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में मजबूती से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। वहीं, इस मामले में भाजपा का कहना है कि जनता कांग्रेस की आवाज सुनना पसंद नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस शांत रहे।

तीन चरणों में कांग्रेस कर रही प्रदर्शन : कांग्रेस इस मुद्दे पर तीन चरणों में आंदोलन कर रही है। पार्टी की रणनीति के

अनुसार 17 जून को सभी जिला मुख्यालयों में बिजली कार्यालयों का घेराव किया गया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। दूसरे चरण में 18 जून को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने अपना पक्ष जनता के सामने रखा। तीसरे चरण में जुलाई के पहले सप्ताह से अभियान शुरू होगा, जिसमें कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने के समर्थन में आवेदन और समर्थन पत्र भरवाएंगे।

बैज बोले...बिजली बिल बना सबसे बड़ी समस्या

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। लोग बिल सुधार के लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार ने जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाए तो जनता की यह नाराजगी एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकती है।

मानसून सत्र में विधानसभा में घेरेंगे

पार्टी ने घोषणा की है कि आगामी मानसून सत्र में यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार से इस पर जवाब मांगेंगे। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतों के साथ-साथ बिजली दरों में वृद्धि भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा।

भाजपा सरकार ने पांच बार बिजली बढ़ाई

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक पांचवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता और किसान प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी बिल बढ़ने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे यह मुद्दा अब प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी सवाल बन गया है।

जुलाई में साय सरकार का चिंतन शिविर

रायपुर,19 जून 2026। छत्तीसगढ़ की साय सरकार शासन-प्रशासन को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। जुलाई महीने में नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में चिंतन शिविर 3.0 का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत राज्य मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रियों की कार्यप्रणाली को और अधिक दक्ष,आधुनिक और जनकेंद्रित बनाना है। कार्यक्रम में प्रशासनिक प्रबंधन, नीति निर्माण,सुशासन,तकनीकी नवाचार,जनसेवा और विकास से जुड़े कई विषयों पर देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ मंत्रियों को मार्गदर्शन देंगे। बदलते दौर में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

समन्वय और प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी व्यापक मंथन किया जाएगा : शिविर के दौरान मंत्रियों को बेहतर नेतृत्व,निर्णय लेने की क्षमता, योजनाओं की निगरानी और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी व्यापक मंथन किया जाएगा।

आगामी दिनों की रणनीति तय होगी : बताया जा रहा है कि सरकार इस मंच का इस्तेमाल आने वाले सालों की विकास रणनीति तय करने और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए भी करेगी। अलग-अलग विभागों की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा भी इस दौरान की जा सकती है। बता दें कि इससे पहले भी नवा रायपुर स्थित IIM में मंत्रियों के लिए प्रशिक्षण और चिंतन कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। उन कार्यक्रमों से मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार का शिविर अधिक व्यावहारिक और परिणामोन्मुख बनाने की तैयारी है।

हवा भरते समय फटा जेसीबी का टायर,हेल्पर की मौत

धमाके से 15 फीट उछलकर दूर जा गिरे,जबड़ा उखड़ा,3 घायल

बिलासपुर,19 जून 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जेसीबी का टायर फटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। दरअसल,पंचर टायर में हवा भरते समय उस पर 4 लोग बैठे हुए थे, एक शख्स पास में खड़ा था और एक चेयर पर बैठा था। सभी बातचीत कर रहे थे,और टायर में हवा भरा रहा था। तभी अचानक टायर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। उस पर बैठे लोग करीब 10 से 15 फीट हवा में उछल गए। इसी दौरान दुकान के हेल्पर के सिर में चोट लगने और जबड़ा उखड़ने से मौत हो गई। ऑपरेटर, मैकेनिक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र के बोदरी स्थित फॉर्च्यून एलिमेंट की निर्माणाधीन कॉलोनी का है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टायर फटने के बाद लोहे का डिस्क निकलकर 30-40 फीट दूर जा गिरा।

हवा भरने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार सुबह 12 बजे की है। फॉर्च्यून एलिमेंट की निर्माणाधीन कॉलोनी में जेसीबी के टायर की मरम्मत की जा रही थी। पंचर ठीक करने के बाद टायर में हवा भरी जा रही थी। तभी अचानक टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि पास खड़ा हेल्पर करीब 15 फीट तक हवा में उछल गया। जमीन पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

हेल्पर का जबड़ा उखड़ा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना जबरदस्त था कि हेल्पर का जबड़ा उखड़ कर बाहर निकल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उमाकांत कौशिक (22) के रूप में हुई है, जो सीपत का रहने वाला था। इस घटना में जेसीबी ऑपरेटर, मैकेनिक और एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है,जिसमें टायर फटने के बाद हेल्पर,मैकेनिक और दो अन्य व्यक्ति हवा में उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

बलौदाबाजार हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त....

छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब,मचा हड़कंप

बलौदाबाजार,19 जून 2026। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई भीषण हिंसा और आगजनी के मामले में कानूनी प्रक्रिया ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में आरोपी अजय यादव द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने राज्य प्रशासन से मामले के तथ्यों और वर्तमान स्थिति पर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कड़ा रुख और आरोपियों पर गंभीर आरोप : बलौदाबाजार हिंसा मामले में 19 मई 2026 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अमित बघेल और अजय यादव की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। अपने आदेश में अदालत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी कि ये आरोपी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी हैं। उन पर

आरोप है कि उन्होंने 7 से 8 हजार लोगों की हिंसक भीड़ को उकसाया,सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल पर जानलेवा हमले किए। कोर्ट ने इन गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था,जिसके बाद आरोपियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के जरिए चुनौती दी।

हिंसा का तांडवः 15 करोड़ की संपत्ति का हुआ नुकसान : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हुई यह हिंसा राज्य के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक रही है। इस घटना ने पूरे जिले की शांति व्यवस्था को तार-तार कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी से करीब 13 से 15 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक,मुख्य आरोपी अमित बघेल के खिलाफ 17, अजय यादव के खिलाफ 13 और दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ एक आपराधिक मामला पहले से ही लंबित है। इन सभी पर कानून-व्यवस्था को चुनौती देने और हिंसा फैलाने के गंभीर आरोप हैं। यह संपूर्ण विवाद 15-16 मई 2024 की रात गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के पूज्य'जैतखाम' में हुई तोड़फोड़ की घटना से शुरू हुआ था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया,लेकिन समाज के एक वर्ग ने इस कार्रवाई पर असंतोष जताया और न्यायिक जांच की मांग की। गृहमंत्री विजय शर्मा ने जांच की घोषणा भी की,लेकिन 10 जून को कलेक्ट्रेट के सामने हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अब तक 43 अलग-अलग आपराधिक मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया है।

रायपुर-दुर्ग के छात्रों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा,चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

रायपुर,19 जून 2026। नीट री एग्जाम की परीक्षा देने वाले छात्र ध्यान दें। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की टेंशन अब खत्म हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेनों की भीड़ में धक्का नहीं खाना पड़ेगा।

कोरबा-दुर्ग के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें : रेलवे ने परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए स्पेशल मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 20 और 21 जून को चलेंगी। ये ट्रेनें चांपा, जांजगीर-नैला, अकलतरा, बिलासपुर,भाटापारा और तिल्दा-नेवरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए जाएंगी। अगर आप कोरबा या बिलासपुर तरफ से आ रहे हैं, तो ये ट्रेन आपके लिए सबसे सही विकल्प है।

हसदेव एक्सप्रेस का बदला रूट : सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही नहीं,रेलवे ने हसदेव एक्सप्रेस को लेकर भी राहत दी है। परीक्षार्थियों

की सुविधा के लिए 21 जून को हसदेव एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से दुर्ग तक बढ़ाया गया है। जो ट्रेन पहले रायपुर आकर रुक जाती थी, वो अब आगे दुर्ग तक जाएगी। इससे भिलाई और दुर्ग में सेंटर पाने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी।

40 अतिरिक्त जनरल कोच का इंतजाम : अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती। इसे देखते हुए रेलवे ने 10 प्रमुख ट्रेनों में 40 अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का फैसला किया है। बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस और टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी ये कोच जोड़े जा रहे हैं।

4.5 करोड़ का गांजा जब्तः केलों की आड़ में हो रही थी तस्करी,शराब ठेके का मालिक निकला मास्टरमाइंड

महासमुंद,19 जून 2026। छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म करने के लिए 'सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक' मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बसना पुलिस ने 4.5 करोड़ रुपये के गांजा तस्करी सिंडिकेट के मुख्य सरगना और नशा माफिया विनय शर्मा उर्फ पंडित जी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, बसना पुलिस ने 17 अप्रैल को पलसापाली बैरियर पर नाकाबंदी कर एक आयशर माल वाहक वाहन को रोका था। पुलिस को चकमा देने के लिए वाहन में कच्चे केलों के नीचे छिपाकर 29 प्लास्टिक बोरियों में 912.760 किलो अवैध गांजा रखा गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 56 लाख 38 हजार रुपये आंकी गई थी। मौके से पुलिस ने 4 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की थी।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...विशेष परिस्थितियों में हुई चूक पर नहीं लग सकता ब्लैकलिस्टिंग का ठप्पा

बिलासपुर,19 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देश की प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स को बड़ी राहत देते हुए राज्य शासन द्वारा जारी ब्लैकलिस्टिंग और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि कंपनी की जब्त की गई प्रतिभूति राशि तत्काल वापस की जाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हुई

अनुबंधीय चूक को धोखाधड़ी या जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं माना जा सकता। मामला वर्ष 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति से जुड़ा है। प्रदेश में दवा की बढ़ती मांग को देखते हुए सीजीएमएससीएल ने मार्च 2021 में ई-टेंडर जारी किया था। सफल बोलीदाता बनने के बाद सिप्ला को शुरुआत में 5,000 वायल की आपूर्ति का आदेश दिया गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में कंपनी को 6,000, 35,000 और 15,000 वायल के अतिरिक्त ऑर्डर जारी कर दिए गए। इस तरह कंपनी को अल्प समय में करीब 61 हजार वायल की आपूर्ति का दायित्व सौंपा गया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)